www.hindmatamirror.com • वर्ष: 13 • अंक: 40 • ठाणे, मंगलवार 6 अक्टूबर, 2026 • पेज: 8 • मूल्य: 2 रुपए hindmatamirror1@gmail.com

दैनिक ठाणे

हिंदमाता मिरर

RNI. NO. MAHHIN/2011/43060

पैनी नजर, पुख्ता खबर



पेज 8

भुवनेश्वर कुमार बने टीम इंडिया के कप्तान

@HINDMATAOFFICIAL

मेरी कोई बेनामी संपत्ति नहीं: रकुल



पेज 8

सुप्रभात

एकता चापलूसी से स्थापित नहीं की जा सकती। जब तक जीवमात्र के साथ एकता महसूस न हो, तब तक प्रार्थना, उपवास, जप-तप सब थोथी बाते हैं।

- महात्मा गांधी

मौसम का मिजाज

सूर्यास्त (6 अक्टूबर) 6:23 बजे, सूर्योदय (7 अक्टूबर) 6:30 बजे, तापमान: 33 डिग्री से. (धूप खिली रहेगी।)

शॉर्ट स्टोरी

महाराज की जीवनी गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड



हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

परम पूज्य प्रमुखस्वामी महाराज के जीवन पर आधारित 13 खंडों का यह जीवनचरित्र, जो 8,848 पृष्ठों और 21,46,447 शब्दों में विस्तृत है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा एकल लेखक द्वारा लिखित विश्व के सबसे लंबे जीवनचरित्र के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। 'ब्रह्मस्वरूप प्रमुखस्वामी महाराज: विस्तृत जीवन एवं कार्य' शीर्षक वाली इस जीवनी के लेखक संस्कृत विद्वान साधु आदर्शजीवनदास, पीएच.डी. हैं। इसमें बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था के दिवंगत आध्यात्मिक प्रमुख प्रमुखस्वामी महाराज (1921-2016) के 94 वर्षों के जीवन और उनकी विरासत का विस्तृत वर्णन किया गया है।

बीस रुपए के लिए बुजुर्ग की हत्या

हिंदमाता नेटवर्क @ नागपुर

नागपुर के बुटीबोरी इलाके में चप्पल की मरम्मत के 20 रुपए देने को लेकर हुए विवाद में 76 वर्षीय मोची जयसिंह राजाराम भैसवार पर लोहे के औजार से कथित तौर पर हमला कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपी की पहचान दिलीप पवार (35) के रूप में हुई है जिसे शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। पवार चप्पल की मरम्मत कराने के लिए मोची की दुकान पर गया था। काम पूरा होने के बाद भैसवार ने जब मरम्मत के 20 रुपए देने को कहा, तो पवार ने लोहे की त्रिकोणीय निहाई से भैसवार के सिर पर वार कर दिया।

छात्रों से मिलने पुणे आ सकते हैं राहुल गांधी

हिंदमाता नेटवर्क @ पुणे

शरद पवार की एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) में सुधार की मांग को लेकर पुणे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से सात या आठ अक्टूबर को मुलाकात कर सकते हैं। प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच एमपीएससी के अध्यक्ष विवेक भीमनवार के इस्तीफे, परीक्षाओं के प्रारूप सहित विभिन्न मांगों को लेकर पुणे में तीन अलग-अलग स्थानों पर विरोध-प्रदर्शन जारी हैं। रविवार को प्रदर्शन में शामिल होने के बाद पवार ने कहा, अब तक सभी दलों के नेता इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं।

गैरमराठी ड्राइवरों को मंत्री का अल्टीमेटम

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रताप सरनाईक ने सोमवार को ऑटो-रिक्शा, टैक्सी और ऐप-बेस्ड कैब चलाने वाले उन ड्राइवरों से अपील की जो मराठी नहीं बोलते हैं कि वे मराठी सीखने की अनिवार्य शर्त पर लगी मौजूदा रोक का इस्तेमाल भाषा सीखने के मौके के तौर पर करें। 18 अगस्त, 2027 तक इस नियम पर लगी रोक की वजह से भाषा सीखने को नजरअंदाज न करें। वे या तो राज्य के "महाराष्ट्र माझा! मराठी माझी संवाद भाषा!" कैंपेन के दूसरे चरण में शामिल होकर जल्द मराठी भाषा सीखें।

एसआईआर विवाद: चुनाव आयोग दफ्तर के बाहर आज इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, आप ने बनाई दूरी







कोर्ट से रोड तक ज्ञानेश कुमार पर तकरार

- सीईसी के निलंबन पर अंतरिम आदेश पारित करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भेजा नोटिस
- फॉर्म-6 के किसी भी संशोधन को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी नहीं- सीजेआई

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली/ मुंबई

इन दिनों देश में चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष मोर्चा खोले बैठा है। दो अक्टूबर से मुंबई में भी एसआईआर के विरुद्ध लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। पहले शिवाजी पार्क में एसआईआर और सीईसी ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध अभिजीत दीपके ने जोरदार मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में जेन जी का आक्रोश प्रशासन की चूलें हिला गया। इसके बाद उद्धव और राज ठाकरे के नेतृत्व में एमवीए का गर्जना मोर्चा निकला। इसी कड़ी में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग का घेराव करेगा। दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद पार्टी के तेवर इस बार काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस का मकसद सरकार और चुनाव आयोग की नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक मोर्चा खोलना है। 8 अक्टूबर को कांग्रेस का बड़ा मार्च होने वाला है, जिसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सबसे बड़ा जोर इस बात पर है कि इस मार्च में विपक्षी गठबंधन के दूसरे घटक दलों को भी साथ लाया जाए। इस बीच नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सोमवार को साफ कर दिया कि वह 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग के बाहर होने वाले इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन में शामिल नहीं होगी।

आप ने प्रदर्शन से दूरी क्यों बनाई?

संजय सिंह ने कहा कि एसआईआर में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अलग-अलग जगहों पर हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस आंदोलन में अपना बैनर तक इस्तेमाल नहीं कर रही है। पार्टी का मानना है कि यह किसी एक दल का मुद्दा नहीं, बल्कि देश के लोगों से जुड़ा मामला है। इसलिए सभी लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि 6 अक्तूबर का प्रदर्शन इंडिया गठबंधन का है और आम आदमी पार्टी उसका हिस्सा नहीं है।

इंडिया गठबंधन ने क्या तय किया था?

30 सितंबर को 19 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इसके बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं ने फैसला किया कि विपक्षी सांसद 6 अक्टूबर को मार्च निकालकर चुनाव आयोग पहुंचेंगे। गठबंधन के नेता राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े कथित मुद्दों और अनियमितताओं को उठाया जाएगा। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले, महबूबा मुफ्ती और वाम दलों के नेता शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन की 30 सितंबर वाली बैठक में आम आदमी पार्टी और डीएमके शामिल नहीं हुई थीं।

राहुल गांधी के दावे का चुनाव आयोग ने किया फैक्ट चेक

चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए राहुल गांधी के दावे का फैक्ट चेक करते हुए कहा है कि इस पोस्ट में किया गया दावा भ्रामक है। चुनाव आयोग ने कहा, "24 जून 2025 को बिहार में एसआईआर के लिए जारी आदेश चुनाव आयोग के सभी सदस्यों की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किया गया था। इस आदेश को भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई 2026 के अपने फैसले में बरकरार रखा है।"

राहुल गांधी बोले- अब कोई शक नहीं...

वोटर रजिस्ट्रेशन के फॉर्म 6 में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के बीच स्थिति साफ होने के बाद कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में गैरकानूनी और एकतरफा तरीके से बदलाव किया। उन्होंने चुनाव आयोग की 26 सितंबर की प्रेस नोट का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर शेयर किया है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा- अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है कि ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म 6 में गैरकानूनी और एकतरफा तरीके से बदलाव किया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि यह उनके पद का इस्तेमाल कर बीजेपी की मदद करने का एक और सबूत है। राहुल गांधी ने कहा कि वह और इस मामले में शामिल अन्य सभी लोगों को लोकतंत्र पर कथित हमले के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

ज्ञानेश कुमार को सस्पेंड करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस

वोटर लिस्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग भले ही एक संवैधानिक संस्था हो, लेकिन वह देश के कानून और तय नियमों से ऊपर बिल्कुल नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की तीन सदस्यीय बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों साथी चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को नोटिस जारी कर सीधा जवाब तलब किया है। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को तीन सख्त हिदायतें दीं।

न्यूज रिपोर्ट के आधार पर नहीं दे सकते आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि 10 दिन में कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा। अगर कुछ गलत हुआ है, तो हम हमेशा उसे रद्द कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका का आधार जो न्यूज रिपोर्ट है, वह 100% सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है। हम उसके आधार पर कोई आदेश नहीं दे सकते हैं। वकील सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा जाए। कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा। इस मामले पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी।

कानून तोड़ा तो हम हर फैसला पलट देंगे

सुनवाई की शुरूआत में याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने दलील दी कि आयोग के अंदर पूरी बेंच की सहमति के बिना एकतरफा फैसले लिए जा रहे हैं। उन्होंने अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर अदालत ने तुरंत दखल नहीं दिया तो हालात बेहद बिगड़ जाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मीडिया रिपोर्टों के बजाय पूरे प्रामाणिक रिकॉर्ड तलब करने की बात कही, लेकिन साथ ही दो-टूक शब्दों में चेताया। सीजेआई ने कहा कि देश में एक अनिवार्य कानून है और चुनाव आयोग से उम्मीद की जाती है कि वह उसका पूरी तरह पालन करे। अदालत ने दो टूक कहा कि अगर कानून का रत्ती भर भी उल्लंघन हुआ, तो हम उसे पूरी तरह पलट देंगे। जस्टिस बागची ने भी स्पष्ट किया कि अगर रिकॉर्ड से ये साबित हुआ कि सर्वसम्मति के जरूरी नियम को ताक पर रखकर फैसले थोपे गए हैं, तो अदालत उन सभी फैसलों पर तुरंत रोक लगाकर उन्हें गैर-कानूनी घोषित कर देगी।

बदला हुआ फॉर्म-6 हमने पास नहीं किया, दिमाग से निकाल दें

नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में अचानक किए गए बदलावों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। विवाद यह है कि नए वोटर फॉर्म में माता-पिता या पूर्वजों की वंशावली और पुराने रिवीजन से जुड़े एक्स्ट्रा कॉलम ऑनलाइन जोड़ दिए गए, जिसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इस पर खुद चुनाव आयुक्तों के बीच भी मतभेद की खबरें थीं। चीफ जस्टिस ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि ये बात एकदम साफ समझ लें, बदले हुए किसी भी फॉर्म-6 को हमारी कोई मंजूरी नहीं मिली है। बेंच ने निर्देश दिया कि पूरे दस्तावेज पेश किए जाएं ताकि अदालत यह पता लगा सके कि आखिर किसके इशारे पर और किस अधिकार से फॉर्म में यह फेरबदल किया गया।

चुनाव आयुक्तों की 'इम्यूनिटी' पर भी सवाल

सुनवाई के दौरान 2023 के नए कानून की धारा 16 के तहत चुनाव आयुक्तों को मिली कानूनी सुरक्षा (इम्युनिटी) पर भी अदालत ने तीखे सवाल खड़े किए। अब तक इस धारा के तहत चुनाव आयुक्तों पर उनके पद पर रहते हुए लिए गए फैसलों के खिलाफ कोई सिविल या क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने संकेत दिया कि यह कानूनी सुरक्षा कवच असीमित नहीं हो सकता। जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि अगर मामला व्यक्तिगत मनमानी या नियमों की अवहेलना का है, तो चुनाव आयोग के अफसर इस कवच के पीछे नहीं छिप सकते। कोर्ट अब गहराई से परखेगा कि क्या नए प्रावधानों का पालन सही तरीके से हुआ है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तेवर से चुनाव आयोग की स्थिति त्रिशंकु जैसी हो गई है।

सीईसी को पद से हटाया जाना चाहिए: पृथ्वीराज चव्हाण

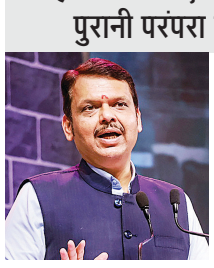
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने ह्यगैरकानूनी तरीके से काम कियाह्ल है और चुनाव आयुक्तों की शक्तियों से संबंधित संसद द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन किया है। चव्हाण ने साथ ही उन्हें निर्वाचन आयोग के शीर्ष पद से हटाने की मांग की। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान ज्ञानेश कुमार ने जो कुछ भी किया है, वह पूरी तरह गैरकानूनी है। उन्होंने संसद द्वारा बनाए गए कानून और चुनाव आयुक्तों की शक्तियों को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लंघन किया है। अगर भारत में लोकतंत्र की रक्षा करनी है, तो उन्हें तुरंत पद से हटा दिया जाना चाहिए।

ज्ञानेश कुमार देश के दुश्मन : संजय राऊत

शिवसेना (उबाठा) के नेता संजय राऊत ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को देश का दुश्मन बताते हुए सोमवार को कहा कि सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दलों के व्यापक विरोध प्रदर्शनों के बाद वह (सीईसी) भूमिगत हो गए हैं। निर्वाचन आयोग को उन विपक्षी सांसदों से मुलाकात करनी चाहिए, जिनके साथ देश के विभिन्न राज्यों में अन्याय हुआ है। इन राज्यों में निर्वाचन आयोग पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मदद करने का आरोप है। राऊत ने आरोप लगाया, ज्ञानेश कुमार देश के दुश्मन हैं। ज्ञानेश कुमार को हमारे सामने आना चाहिए। वह भूमिगत हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञानेश कुमार के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए।

सीएम फडणवीस ने किया एसआईआर का समर्थन

कहा- वर्तमान एसआईआर प्रक्रिया दशकों पुरानी परंपरा का ही अगला चरण



महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया का समर्थन किया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि एसआईआर कोई नई बात नहीं है। बल्कि, ये एक जरूरी प्रक्रिया है, जिसे चुनाव आयोग दशकों से समय-समय पर अपनाता रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया- ''भारत की चुनावी व्यवस्था में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया कई दशकों से चली आ रही है। मतदाता सूचियां सटीक और विश्वसनीय बनी रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने विभिन्न चरणों में इन सूचियों का गहन संशोधन किया है।''

एसआईआर प्रक्रिया का इतिहास बताया

इस दौरान सीएम फडणवीस ने एसआईआर प्रक्रिया का इतिहास बताया। उन्होंने पोस्ट किया- ''1952 से 1956 की अवधि में चुनाव आयोग ने देश के अधिकांश हिस्सों में मतदाता सूचियों का व्यापक पुनरीक्षण किया। उसके बाद 1957, 1961, 1965 और 1966 में भी देश के अधिकांश हिस्सों में पुनरीक्षण किया गया। आगे 1983-84, 1987-89, 1992, 1993 और 1995 की अवधि में भी वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर बदलाव किए। चुनाव आयोग ने 2002, 2003 और 2004 में फिर से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया।''

16 अक्टूबर से 10% पानी की कटौती

- समूचे महाराष्ट्र में सभी ग्रामीण और शहरी निकायों में होगी जल कटौती
- सूखा संकट के बीच सड़कें धोने पर 8.25 करोड़ खर्च करने की तैयारी



हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को कहा कि वह कम मानसून के बीच 16 अक्टूबर से सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में 10 प्रतिशत जल कटौती लागू करेगी। राज्य के जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि उनके विभाग ने 31 अगस्त, 2027 तक के लिए उपलब्ध जल भंडार को लेकर बांधवार और उपयोगिता अनुसार विस्तृत योजना बनाई है जिसमें अल-नीनो के प्रभाव को और सूखे जैसे हालात की संभावना को ध्यान में रखा गया है। महाजन ने कहा कि पेयजल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को 16 अक्टूबर से 10 प्रतिशत पानी की कटौती लागू करने का निर्देश दिया गया है।

10 प्रतिशत अतिरिक्त आपात बफर स्टॉक रखा जाएगा

महाजन ने कहा कि सरकार ने स्थानीय निकायों को पानी के रिसाव को रोकने और जलमल शोधन संयंत्रों को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के लिए भी विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उद्योगों को उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले कम से कम 30 प्रतिशत पानी का पुन: उपयोग करने का निर्देश भी दिया गया है। प्रत्येक बांध में 10 प्रतिशत अतिरिक्त आपात बफर स्टॉक रखा जाएगा। वाष्पीकरण, गाद (तलछट) और अनधिकृत निकासी का हिसाब लगाने के बाद, 31 अगस्त, 2027 तक पीने के पानी की आवश्यकता को आरक्षित रखा जाएगा।

... तो उपकरणों को जब्त कर लिया जाएगा

पीने के पानी, मवेशियों और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। मंत्री ने राज्य के नागरिकों और सरकारी एजेंसियों से जल का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जल संसाधन, राजस्व, कृषि, उद्योग और शहरी विकास विभाग हालात से निपटने के लिए तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अधिकारी राजस्व और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर बांधों, नदियों और नहरों से अवैध तरीके से पानी निकाले जाने पर रोकथाम के लिए गश्त करेंगे और अवैध पंपों तथा उपकरणों को जब्त कर लिया जाएगा।

सड़कें धोने पर 8.25 करोड़ खर्च करने की तैयारी

एक तरफ महाराष्ट्र सूखे के संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर देश की सबसे अमीर महानगरपालिका कही जाने वाली मुंबई महानगरपालिका अब सड़कों को पानी से धोने के लिए 8 करोड़ 25 लाख 33 हजार 48 रुपए खर्च करने जा रही है। इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीएमसी ने शहर की सड़कों को पानी से धोने के लिए 8 करोड़ 25 लाख 33 हजार 48 रुपए का ठेका निकाला है। मुंबई के सातों परिमंडलों में 150 दिनों तक रोज सड़कें धोई जाएंगी।

48 दिन से आंदोलन, 13 दिन अनशन... मुंबई में आदिवासी छात्रों का हल्ला बोल

कांग्रेस का दावा, आदिवासी छात्रों को हिरासत में लिया गया



हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने आरोप लगाया कि सोमवार तड़के पुलिस ने कई आदिवासी छात्रों को रोककर हिरासत में ले लिया। ये छात्र आदिवासी विकास मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर आजाद मैदान में प्रदर्शन करने मुंबई आए थे। विपक्षी दल ने कहा कि धमकियों से छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और वह आदिवासी छात्रों के जायज अधिकारों के लिए संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए पार्टी ने एक बयान में कहा, छात्रों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करने के बजाय उन्हें धमकाना और पुलिस बल का इस्तेमाल करना लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाने के समान है। कांग्रेस का आरोप है कि मुंबई पुलिस ने तड़के करीब तीन बजे छात्रों को रोका, उनकी तस्वीरें लीं और उन्हें हिरासत में ले लिया।

हिंदमाता एंकर: दिमागी कोशिकाओं को कंट्रोल करने की तकनीक पर मेडिसिन नोबेल, जर्मनी-अमेरिका के तीन वैज्ञानिकों की रिसर्च, डिप्रेशन और मानसिक बीमारियों को समझना आसान हुआ, इलाज में मिलेगी मदद

दिमाग की गतिविधि पर रिसर्च के लिए तीन वैज्ञानिकों को मिला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार

हिंदमाता नेटवर्क @ स्टॉकहोम

चिकित्सा के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार का ऐलान सोमवार को कर दिया गया है। इस साल ये सम्मान तीन लोगों- कार्ल डाइसेरोथ (54), पीटर हेगेमैन (71) और जॉर्ज नागेल 73 को दिया गया है। इस पुरस्कार का ऐलान सोमवार को स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में किया गया है। इसके साथ ही नोबल पुरस्कारों के हफ्ते की शुरुआत भी हो गई है।

किस योगदान के लिए मिला नोबल?



कार्ल डाइसेरोथ, पीटर हेगेमैन और जॉर्ज नागेल को लाइट-गेटेड आयन चैनल और ऑप्टोजेनेटिक्स पर उनकी रिसर्च के लिए चिकित्सा के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन तीनों वैज्ञानिकों ने इस बात पर रिसर्च की है कि मस्तिष्क व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिकाओं (नर्व सेल्स) की गतिविधियों को चालू या बंद करने के लिए किन सिस्टम का उपयोग करता है। ये तीनों वैज्ञानिक जर्मनी और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं।

1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलेंगे

सामने आई जानकारी के अनुसार, इस साल नोबल पुरस्कार की राशि 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (करीब 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रखी गई है।

एक कोशिका वाले शैवाल से शुरू हुई खोज

इस खोज की शुरूआत पीटर हेगेमान की जिज्ञासा से हुई। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि एक कोशिका वाला शैवाल क्लैमाइडोमोनास प्रकाश के स्रोत की ओर कैसे तैरता है। शैवाल या एल्गी ऐसे सरल जीव हैं जो आमतौर पर पानी में पाए जाते हैं और प्रकाश की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। इनमें एक कोशिका से लेकर कई कोशिकाओं तक की संरचना हो सकती है. काई से ये अलग होते हैं. काई आमतौर पर जमीन पर उगने वाले छोटे पौधेनुमा जीव होते हैं जबकि शैवाल ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं और उनका पौधों से सीधा संबंध नहीं होता।

चैनलरोडॉप्सिन प्रोटीन की खोज

2000 के दशक की शुरूआत में हेगेमान और जॉर्ज नागेल ने चैनलरोडॉप्सिन नाम के एक प्रोटीन की खोज की। यह प्रोटीन शैवाल की कोशिका की सतह पर पाया जाता है। जब इस पर नीली रोशनी डाली जाती है तो प्रोटीन में एक चैनल खुल जाता है। इसके बाद आवेशित आयन कोशिका के भीतर जाने लगते हैं और एक विद्युत संकेत (इलेक्ट्रिकल इंपल्स) पैदा होता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस प्रोटीन को जिस भी कोशिका में डाला गया वह प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो गई। यही खोज आगे चलकर न्यूरॉन्स को प्रकाश की मदद से नियंत्रित करने की तकनीक का आधार बनी।

न्यूरॉन्स के लिए बनाया प्रकाश का स्विच

कार्ल डाइसरॉथ ने चैनलरोडॉप्सिन के जीन को चूहों की न्यूरॉन्स में पहुंचाया। नीली रोशनी डालकर वे इन कोशिकाओं में तंत्रिका संकेत पैदा करने में सफल रहे। उन्होंने 2005 में इस खोज को पब्लिश किया। इसके दो साल बाद उन्होंने जीवित चूहों के मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं को प्रकाश की मदद से नियंत्रित करने में सफलता हासिल की। इस तकनीक को आगे चलकर ऑप्टोजेनेटिक्स कहा गया। ऑप्टोजेनेटिक्स ने मस्तिष्क के अध्ययन का तरीका बदल दिया। इसके जरिए शोधकर्ता उन तंत्रिका सर्किटों की पहचान कर सके हैं जो खास यादों, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। इससे न्यूरोलॉजिकल और दिमाग से जुड़ी बीमारियों को समझने के नए रास्ते खुले हैं।

फर्जी एप से 15.75 करोड़ की ठगी, 2,805 फर्जी एपीके बनाए

सॉफ्टवेयर डेवलपर गिरफ्तार

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई



मुंबई क्राइम ब्रांच ने फर्जी एपीके फाइल्स बनाकर साइबर ठगों के अलग-अलग गिरोहों को बेचने वाले एक अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के मुख्य सरगनाथ का पदार्फाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 36 साल के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने अब तक 2,805 फर्जी एपीके फाइल्स तैयार कर साइबर अपराधियों के अलग-अलग गिरोहों को बेची थीं। इन फर्जी फाइल्स के जरिए देशभर में करीब 9,673 लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक, इन मामलों में अब तक करीब 15 करोड़ 75 लाख रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है।

सीनियर सिटीजन कार्ड का झांसा

इस मामले का बैकग्राउंड 13 अगस्त से जुड़ा हुआ है, जब 72 साल के एक बुजुर्ग के पास अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को बैंक ऑफ इंडिया का सीनियर मैनेजर दिनेश कुमार बताते हुए बुजुर्ग को सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने का झांसा दिया। बातचीत के दौरान उसने बुजुर्ग का भरोसा जीत लिया और उनके व्हाट्सऐप पर 'सीनियर सिटीजन कार्ड वेरिफिकेशन' नाम से एक एपीके फाइल भेजी। इसके बाद बुजुर्ग से इस फाइल में अपनी निजी जानकारी और डेबिट कार्ड की जानकारी भरने को कहा गया। जैसे ही उन्होंने जानकारी भरी, उनके बैंक खाते से 5 लाख 62 हजार रुपए निकाल लिए गए।

तकनीकी जांच से आरोपी तक पहुंची पुलिस

ठगी का पता चलने के बाद पीड़ित ने भायखला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बाद में मुंबई पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई। डीसीपी राज तिलक रौशन ने बताया कि ठगी में इस्तेमाल की गई एपीके फाइल की तकनीकी जांच के दौरान पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में अहम सुराग मिले। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने मध्य प्रदेश से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के दफ्तर पर छापे के दौरान पुलिस ने एक पेनड्राइव, एक सीपीयू, तीन हार्ड डिस्क, एक वाई-फाई राउटर और तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं। शुरूआती जांच में पता चला है कि आरोपी अलग-अलग कंपनियों के सर्वर का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस को शक है कि इन्हीं के जरिए वह फर्जी एपीके फाइल्स तैयार कर उन्हें साइबर ठगी करने वाले गिरोहों तक पहुंचाता था।

धमकी से गरमाई उल्हासनगर की राजनीति

●शिवसेना ने डीसीपी से की कार्रवाई की मांग, कहा- जरूरत पड़ी तो देंगे जवाब

हिंदमाता संवाददाता @ उल्हासनगर



भाजपा और शिवसेना के बीच गठबंधन तोड़ने के अटकलों के बाद उल्हासनगर की राजनीति में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। महापौर अश्विनी निकम के पति कमलेश निकम पर टिकाटिप्पणी के बाद भाजपा पदाधिकारियो द्वार सोशल मीडिया के माध्यम से कथित रूप से मारपीट की धमकी दिए जाने के बाद शहर का राजनीतिक माहौल गरमा गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सोमवार शाम शिवसेना का एक प्रतिनिधिमंडल पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) सचिन गोरे से मिला और दोषियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की।

सोशल मीडिया पर धमकी

जानकारी के अनुसार गठबंधन टूटने के बाद दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। इसी दौरान कमलेश निकम द्वारा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण पर विवादित टिप्पणी किए जाने के बाद भाजपा पदाधिकारी कपिल अडसुल, मनीष हिंगोरानी तथा अन्य लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर कथित रूप से धमकी भरे वीडियो जारी किए गए। इसके बाद देर रात महापौर के निवास के बाहर कुछ संदिग्ध लोगों के जमा होने की सूचना से क्षेत्र में तनाव फैल गया। स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में शिवसेना पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए, जबकि पुलिस ने तत्काल पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली।

डीसीपी से कार्रवाई की मांग

सोमवार को डीसीपी सचिन गोरे से मुलाकात के दौरान शिवसेना नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा के कपिल अडसुल, मनीष हिंगोरानी एवं अन्य लोगों की गतिविधियों से शहर का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा शिवसेना अपने अंदाज में जवाब देने से पीछे नहीं हटेगी।

शिवसेना पदाधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर महापौर अश्विनी निकम, शिवसेना नेता राजेंद्र चौधरी, राजेंद्र सिंह भुल्लर, रमेश चव्हाण, कुलवंत सिंह सोहता, पंचम कलानी, दुर्गा रॉय, सुमित चक्रवर्ती, कुमारी ठाकुर, पंकज त्रिलोकनी, मोनू सिद्दीकी, नरेंद्र कुमारी सहित बड़ी संख्या में नगरसेवक एवं शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित रहे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

गलत स्पीड ब्रेकर से बढ़ी परेशानी

धांगे हॉस्पिटल से धामणकर नाका तक 1.78 किमी में 18 ब्रेकर

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी



भिवंडी शहर में स्कूलों-अस्पतालों के पास ब्रेकर लगाने के बजाय मनपा निर्माण विभाग ने एक ही मार्ग पर ऊंचे प्लास्टिक ब्रेकर लगा दिए हैं। नागरिकों का आरोप है कि इनसे वाहन चालकों को कमर, गर्दन और रीढ़ में चोट की शिकायतें हो रही हैं। उन्होंने अपायकारक ब्रेकर तत्काल हटाने की मांग की है।

1.78 किमी में 18 ब्रेकर

केसरबाग, जुना ठाणा रोड पर धांगे हॉस्पिटल से धामणकर नाका तक 1.78 किमी सड़क का कुछ दिन पहले ही आरसीसी कंक्रीटीकरण हुआ है। इसके बाद सड़क पर ड्रिल कर 18 प्लास्टिक/फाइबर ब्रेकर लगाए गए हैं। धांगे हॉस्पिटल के पास कुंभारवाडा गली से बोबडे मार्ग तक 50-60 मीटर की दूरी में ही सात ब्रेकर लगाए गए हैं, जबकि स्थानीय लोगों के अनुसार यहां न स्कूल है और न अस्पताल।

ऊंचाई और स्लोप पर सवाल

स्थानीय लोगों ने मनपा प्रशासन से शिकायत की है कि ब्रेकर की ऊंचाई अधिक है और स्लोप ईंट जैसा सीधा है। इससे वाहन उछलने और बाइक सवारों के गिरकर घायल होने का खतरा बना रहता है। रोजाना इस मार्ग से गुजरने वाले ऑटो, कार और बाइक चालकों को जोरदार झटके लग रहे हैं, जिससे स्लिप डिस्क का खतरा बढ़ने की बात कही जा रही है।

नियमों के अनुसार जांच की मांग

जागरूक नागरिक अविनाश सिकची ने मनपा से ब्रेकर की ऊंचाई-चौड़ाई और उनके बीच की दूरी की सरकारी नियमों के अनुसार जांच कराने की मांग की है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से हड्डी के सर्जन डॉक्टरों की रिपोर्ट लेने तथा प्लास्टिक ब्रेकर हटाकर सही स्लोप वाले नियमानुसार डामरी ब्रेकर लगाने की मांग की।

अन्य मार्गों पर भी शिकायत

स्थानीय लोगों के अनुसार शहर के अन्य आरसीसी मार्गों पर भी ऐसी ही स्थिति है। पद्मनगर सब्जी मार्केट में 50 मीटर के अंतराल में आधा दर्जन स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं। मनपा निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता सचिन नाईक ने कहा कि सड़कों पर जाकर मौके की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

अणिक डिपो में आग

सीएनजी बसों तक पहुंची आग

किसी के घायल होने की सूचना नहीं

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई



सेंट्रल मुंबई में बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति एवं परिवहन (बेस्ट) के अनिक बस डिपो में सोमवार शाम भीषण आग लग गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने प्रारंभिक जानकारी के हवाले से बताया कि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

बसें आग की चपेट में

बेस्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि आग शाम करीब 5.45 बजे अनिक डिपो के परिसर में लगी, जिसकी चपेट में कतार में खड़ी कुछ सीएनजी चलित बसें आ गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटनास्थल पर धमाकों की आवाज सुनाई देने का दावा किया जबकि दूर से भी धुएं का काला गुबार दिखाई दे रहा था।

दमकल ने संभाला मोर्चा

एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई दमकल विभाग के कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। आग लगने के कारण का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

बाणगंगा में सैकड़ों मछलियां मृत

पूजा-सामग्री विसर्जन के बाद मछलियों की मौत

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई



दक्षिण मुंबई के ऐतिहासिक बाणगंगा तालाब में मरी हुई सैकड़ों मछलियां पानी की सतह पर उतराती पाई गईं। माना जा रहा है कि 'पितृ पक्ष' के दौरान वहां पूजा-सामग्री आदि विसर्जित करने के बाद ऐसा हुआ, जिसके बाद नगर निगम ने उस जगह की सफाई और बाकी जलीय जीवों को बचाने के लिए कदम उठाए हैं। बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के 'डी' वार्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पानी में विसर्जित पूजा-सामग्री हटाने का काम शुरू हो गया है।

ऑक्सीजन स्तर बढ़ाने के उपाय

उन्होंने कहा कि पानी की जांच करने और ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने तथा तालाब में जलीय जीवों को और नुकसान से बचाने के उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ को भी बुलाया गया था। बाणगंगा तालाब में मछलियों की हर साल मौत चिंता का विषय बन गई है। पिछले साल पितृ पक्ष के दौरान भी ऐसा ही हुआ था।

ऐतिहासिक और संरक्षित तालाब

वालकेश्वर स्थित यह तालाब ऐतिहासिक बाणगंगा परिसर का हिस्सा है और एक संरक्षित विरासत संरचना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, माना जाता है कि भगवान राम ने इसी जगह पर पूर्वजों के लिए अंतिम संस्कार से जुड़ा अनुष्ठान 'पिंड दान' किया था। 'वालकेश्वर' नाम संस्कृत शब्दों 'वालुका' (रेत) और 'ईश्वर' से मिलकर बना है और यह इस जगह पर रेत से शिवलिंग बनाने की कथा से संबंधित है।

दुष्कर्म दोषी को 20 साल की सजा

भिवंडी कोर्ट का फैसला, 5 हजार जुमार्ना

बच्ची को धमकी देने का भी आरोप

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी



10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में भिवंडी की अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने आरोपी रवि बजरंग तुम्मा (53) को 20 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है। जुमार्ना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

कमरे में ले जाकर वारदात

पुलिस के अनुसार घटना 14 मई 2023 को दोपहर करीब 2:30 बजे की है। बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी उसे कमरे में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

पुलिस ने जुटाए साक्ष्य

भोईवाड़ा पुलिस ने संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन.के. कारंडे की अदालत में हुई।जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक रामेश्वर दराडे और पुलिस टीम ने सरकारी अधिवक्ताओं के माध्यम से अदालत में ठोस साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने शनिवार को आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। यह जानकारी भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विक्रम मोहिते ने दी।

ऑटो में छूटा 16 तोला सोना और नगदी

विष्णुनगर पुलिस ने ढूंढकर महिला को लौटाया

हिंदमाता संवाददाता @ कल्याण



डोंबिवली की विष्णुनगर पुलिस की डिटेक्शन ब्रांच टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए एक महिला को 16 तोला सोने के गहने और 1 लाख 20 हजार रुपए सफलतापूर्वक वापस दिलाए। महिला ऑटो-रिक्शा में यात्रा करते समय ये चीजें वहीं भूल गई थी। पुलिस की तत्परता और इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार एक महिला गलती से ऑटो-रिक्शा में 16 तोला सोने के गहने और 1 लाख 20 हजार की नकद रकम छोड़ आई थी। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने विष्णुनगर पुलिस से संपर्क किया।

पुलिस की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई

मामले की गंभीरता को समझते हुए, डीबी टीम के पुलिस कांस्टेबल निकुले और पुलिस नाइक कसबे ने तुरंत जांच शुरू की। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हुए, उन्होंने इलाके की विभिन्न जगहों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इस फुटेज की मदद से पुलिस ने संबंधित ऑटो-रिक्शा का पता लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने ऑटो-रिक्शा को ढूंढा और 16 तोला सोने के गहने व 1 लाख 20 हजार नकद बरामद किए। सभी कीमती सामान महिला को वापस कर दिया गया।

जनता के लिए सतर्कता और सावधानी के निर्देश

इस घटना के बाद विष्णुनगर पुलिस ने नागरिकों, विशेषकर महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण परामर्श जारी किया है। पुलिस ने अपील की है कि सार्वजनिक या निजी परिवहन (जैसे ऑटो, टैक्स) में सफर करते समय अपने कीमती सामान और बैग का विशेष ध्यान रखें। ऑटो या टैक्सी में बैठते ही उसका नंबर नोट कर लें या अपने परिजनों को मैसेज कर दें। किसी भी आपात स्थिति या सामान छूट जाने पर बिना देरी किए तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, ताकि समय रहते त्वरित कार्रवाई की जा सके।

प्रधानाचार्य ने नाबालिग छात्रा के साथ बंद कमरे में की घिनौनी हरकत

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला

हिंदमाता नेटवर्क @ लातूर



लातूर में सोमवार को एक स्कूल के संस्थापक-एवं-प्रधानाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन किया गया जिस पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ करने का आरोप है। प्रदर्शनकारियों ने यहां निजी अंग्रेजी स्कूल आदर्श एजुकेशनल कैंपस के संस्थापक-सह-प्रधानाचार्य बशीर शेख के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। रविवार रात उसके खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत एमआईडीसी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। प्राथमिकी के अनुसार, उसने कथित तौर पर 20 सितंबर को एक छात्रा को स्कूल परिसर में स्थित एक कमरे में बुलाया और उसके साथ अनुचित व्यवहार किया। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं, उन्होंने कहा कि शेख को शिक्षक पेशे को बदनाम करने और छात्रों तथा शिक्षकों के बीच विश्वास को नुकसान पहुंचाने के लिए फांसी दी जानी चाहिए। इस बीच, वासवाड़ी-बार्शी रोड इलाके में स्थित स्कूल की शाखा के खिड़कियों के शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए गए और अज्ञात लोगों ने नामपट्ट पर स्याही फेंक दी। एमआईडीसी पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि शेख को पकड़ने के लिए कई टीम गठित की गई हैं।

शॉर्ट स्टोरी

104 बुजुर्गों को मिलेंगे सहायक उपकरण

हिंदमाता संवाददाता @ विरार



वसई-विरार महानगरपालिका के सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक न्याय विभाग की ओर से 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत प्रभाग समिति बी, डी और एफ के वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। 2 अक्टूबर को नालासोपारा पूर्व स्थित प्रभाग समिति डी कार्यालय में आयोजित शिविर में 114 वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। महानगरपालिका और एलिम्को, मुंबई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित शिविर में विशेषज्ञों ने बुजुर्गों की स्वास्थ्य जांच कर उनकी जरूरत के अनुसार सहायक उपकरणों के लिए चयन किया। इनमें 104 पात्र वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण किया गया। इन्हें व्हीलचेयर, वॉकर, श्रवण यंत्र, लाठी और ट्राइपॉड जैसे उपकरण निःशुल्क दिए जाएंगे। प्रशासन ने बताया कि आने वाले दिनों में अन्य प्रभाग समितियों में भी ऐसे शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविर महापौर अजीव पाटिल, उप-महापौर मार्शल लोपिस और आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ।

नवरात्रोत्सव की तैयारी शुरू

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी



गणेशोत्सव के बाद शहर में नवरात्रोत्सव की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं। भिवंडी के श्री रंग नगर स्थित रवि पाटिल कंपाउंड में ॐ जय बाबा मित्र मंडल की ओर से 19वें सार्वजनिक नवरात्रोत्सव के लिए शनिवार को पंडाल निर्माण का भूमिपूजन किया गया। पंडित सुरेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत पूजा कराई। भूमिपूजन के बाद रात आठ बजे से 12 बजे तक रवि तिवारी एंड कंपनी की ओर से संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन किया गया। इसके बाद भजन और आरती हुई तथा भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मंडल अध्यक्ष पत्रकार जितेंद्र तिवारी ने बताया कि इस वर्ष भी सार्वजनिक नवरात्रोत्सव बंगाली पद्धति से आयोजित किया जाएगा। दुर्गा प्रतिमा तैयार करने का कार्य बंगाल से आए परेश पॉल कर रहे हैं। शहर के अन्य मंडलों ने भी भूमिपूजन कर पंडाल निर्माण शुरू कर दिया है।

सड़क निर्माण की मांग

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी



भिवंडी रेलवे स्टेशन और तडाली जकात नाका के बीच 1980 से उपयोग में आ रही सड़क रखरखाव के अभाव में जर्जर होकर बंद हो गई है। इससे तडाली गांव के ग्रामीणों और किसानों में भारी नाराजगी है। स्थानीय भाजपा नगर सेवक नीलेश चौधरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने रेलवे स्टेशन मास्टर को ज्ञापन देकर सड़क के तत्काल निर्माण की मांग की। ग्रामीणों के अनुसार रेलवे लाइन निर्माण के दौरान कृषि कार्य और आवागमन के लिए 30 फीट चौड़ी सड़क स्वीकृत की गई थी। लेकिन समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर की परियोजनाओं के कारण सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। अब किसानों के लिए खेतों तक पहुंचना और ग्रामीणों के लिए रेलवे स्टेशन जाना मुश्किल हो गया है। नीलेश चौधरी ने रेलवे प्रशासन से भिवंडी रेलवे स्टेशन से तडाली जकात नाका तक कम से कम 30 फीट चौड़ी सड़क का तत्काल निरीक्षण कर निर्माण कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सड़क नहीं बनने पर नागरिकों और किसानों की परेशानी बढ़ती रहेगी।

कार्रवाई पर आरपीआई का विरोध

हिंदमाता संवाददाता @ भिवंडी



अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए आरपीआई एकतावादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विकास निकम ने संबंधित मनपा अधिकारी को तत्काल निलंबित कर गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने रविवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नगर निगम ने 29 सितंबर को तीनबत्ती इलाके में स्थित पार्टी कार्यालय के केबिन को अनधिकृत घोषित कर ध्वस्त किया था। निकम ने आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान शहर विकास अधिकारी साकिब खरबे ने अनुसूचित जाति समुदाय के प्रति आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उनकी शिकायत पर नगर पुलिस स्टेशन में अत्याचार का मामला दर्ज होने के बावजूद गिरफ्तारी और निलंबन नहीं हुआ है। निकम ने आरोप लगाया कि शहर में कई राजनीतिक दलों के अनधिकृत कार्यालय और निर्माण हैं, लेकिन कार्रवाई केवल आरपीआई कार्यालय पर की गई। उन्होंने साकिब खरबे और वार्ड समिति क्रमांक 5 के सहायक आयुक्त गिरीश गोष्टीकर के निलंबन तथा अन्य अनधिकृत निमार्णों पर कार्रवाई की मांग की। मांगें पूरी नहीं होने पर धरना आंदोलन की चेतावनी दी।

अनूप अग्रवाल ने संभाला अतिरिक्त कार्यभार

प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर के साथ मध्य रेल के अपर महाप्रबंधक की अतिरिक्त जिम्मेदारी

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई



अनूप कुमार अग्रवाल ने 1 अक्टूबर 2026 को अपने वर्तमान दायित्व प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर के साथ मध्य रेल के अपर महाप्रबंधक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातकोत्तर हैं और 1988 बैच के भारतीय रेल विद्युत इंजीनियर सेवा के अधिकारी हैं।

38 वर्षों का अनुभव

अग्रवाल ने करियर की शुरूआत उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे में सहायक विद्युत इंजीनियर के रूप में की। 38 वर्ष के सेवाकाल में उन्होंने भारतीय रेल के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। मुंबई में उन्हें 10 वर्ष से अधिक का अनुभव है। उन्होंने मुंबई मंडल के कलवा, कुर्ला और कल्याण सहित मुख्यालय में भी महत्वपूर्ण पद संभाले हैं।

एमयूटीपी परियोजना में योगदान

नवंबर 2011 से जुलाई 2017 तक मुंबई रेल विकास निगम में प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्होंने विश्व बैंक वित्तपोषित एमयूटीपी-द्वितीय परियोजना के तहत 72 ईएमयू रेक की खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में भी उन्होंने विद्युत योजनाओं और परिचालन की जिम्मेदारी संभाली। अब वे अपने अनुभव से मध्य रेल के विकास और कार्यकुशलता बढ़ाने में योगदान देंगे।

मेयर के पति के बयान पर उत्तर भारतीय नाराज

हिंदमाता संवाददाता @ उल्हासनगर

शिवसेना (शिंदे) नेता एवं उल्हासनगर मनपा की महापौर अश्विनी निकम के पति कमलेश निकम के भाजपा अध्यक्ष विधायक रविंद्र चव्हाण के बारे में दिए गए विवादित बयान को लेकर उत्तराभारतीय में आक्रोश बढ़ता जा रहा हैं। उल्हासनगर भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के जिलाध्यक्ष राकेश पाठक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक पत्रकार परिषद आयोजित कर तीखा पलटवार किया। पाठक ने आरोप लगाया कि निकम की बयानबाजी से उत्तर भारतीय समाज में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है और हम कमलेश निकम का काला मुंह करके शहर में घुमाने वाले है। और आने वाले चुनाव में शिवसेना को इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।

शिवसेना भाजपा में चरम पर पहुंची कलह

उन्होंने निकम की राजनीतिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और कब किस राजनीतिक दल के साथ खड़े नजर आएंगे, इसका किसी को पता नहीं रहता। पाठक ने आरोप लगाया कि निकम पहले जिन लोगों के खिलाफ बयान देते हैं, बाद में उन्हीं के साथ खड़े होकर माफी मांगते हैं और यह सफाई देते हैं कि उन्हें साहब के कहने पर बोलना पड़ा था।

हिंदमाता एंकरः सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द, रमेश म्हात्रे सहित चार आरोपी फिर पहुंचे जेल

डोंबिवली अस्पताल मारपीट केस

हिंदमाता संवाददाता @ डोंबिवली



डोंबिवली के शास्त्रीनगर अस्पताल में डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों से कथित मारपीट के मामले में नगरसेवक रमेश सुक या म्हात्रे सहित चार आरोपियों को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद चारों ने कल्याण कोर्ट में हाजिर होकर आत्मसमर्पण किया। न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में कल्याण की आधारवाड़ी जेल भेज दिया गया। यह मामला 6 जुलाई 2026 को केडीएमसी के शास्त्रीनगर अस्पताल में हुआ था। प्रसूति के लिए आई एक महिला को अस्पताल में एनआईसीयू की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी गई थी। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि रमेश म्हात्रे अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों तथा कर्मचारियों से गाली-गलौज व मारपीट की।

ते म्हात्रे गोवा चले गए थे

इसके बाद विष्णुनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। बाद में रमेश म्हात्रे को जमानत मिली, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें दोबारा हिरासत में जाना पड़ा। इसके बाद हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत मंजूर की थी। आरोपपत्र दाखिल होने तक महाराष्ट्र से बाहर रहने की शर्त के चलते म्हात्रे गोवा चले गए थे।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बदला घटनाक्रम

राज्य सरकार और शिकायतकर्ता पक्ष ने जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 28 सितंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश म्हात्रे समेत चार आरोपियों की जमानत रद्द कर निर्धारित अवधि में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। अदालत ने डॉक्टरों और मेडिकल कर्मचारियों पर हिंसा के मामले को गंभीरता से लेते हुए सार्वजनिक सेवा से जुड़े कर्मचारियों के साथ हिंसा को स्वीकार नहीं किए जाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लोकप्रतिनिधि कानून से ऊपर नहीं हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई 6 महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।

जमानत रद्द होने के बाद किया आत्मसमर्पण

पुलिस ने इस मामले में रमेश म्हात्रे के अलावा रमेश पवार, प्रमोद निकम, अक्षय करंडे और साधना करंडे के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। जांच में डॉक्टरों, नर्सों और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के साथ सीसीटीवी फुटेज समेत अन्य सबूत जुटाए जाने का पुलिस ने दावा किया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द किए जाने के बाद म्हात्रे समेत चार आरोपियों की दोबारा न्यायिक हिरासत में रवानगी हुई है। अब मामले की आगे की सुनवाई कल्याण न्यायालय में होगी।

छात्रों का आधा सिर मुंडवाकर छोड़ा, मचा बवाल

स्कूल बोला- ट्रिमर की बैटरी खत्म हो गई थी

हिंदमाता नेटवर्क @ चंद्रपुर



चंद्रपुर जिले के चिमूर तहसील के जांभुलघाट स्थित सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक निवासी आश्रमशाला में छात्रों के बाल काटने का मामला विवादों में आ गया है। आरोप है कि शनिवार को करीब 80 बच्चों के सिर के आधे बाल ट्रिमर से काट दिए गए और बाकी बाल बाद में काटने की बात कहकर उन्हें छोड़ दिया गया। आधे मुंडे सिर वाले छात्रों की तस्वीरें सामने आने के बाद मामला गरमा गया। इसके बाद रात में ही बच्चों के बाल दोबारा काटे गए। जांभुलघाट की इस आश्रमशाला में पहली से 11वीं कक्षा तक करीब 572 विद्यार्थी निवासी रहकर पढ़ाई करते हैं। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक, छात्रों के सिर में डैंड्रफ और खुजली की समस्या को देखते हुए बाल काटने का फैसला लिया गया था। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे कटिंग शुरू हुई। आरोप है कि शुरूआत में कुछ छात्रों के सिर के बाल का आधा हिस्सा ही ट्रिमर से काटा गया। इसी बीच ट्रिमर की चार्जिंग खत्म होने और बाकी कटिंग बाद में करने की बात सामने आई। इसी दौरान आधे मुंडे सिर वाले बच्चों की तस्वीरें वायरल हो गईं।

रात 11 बजे शुरू हुई कटिंग

तस्वीरें सामने आने के बाद आश्रमशाला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आश्रमशाला के अधीक्षक प्रशांत मेश्राम के मुताबिक, उन्हें ऑफिस से फोन आया और बच्चों के बाल तुरंत लेवल करने के निर्देश दिए गए। इसके बाद रात करीब 11 बजे छात्रों के बाल दोबारा काटने का काम शुरू किया गया, जो सुबह करीब 4 बजे तक चलता रहा। बताया जा रहा है कि इस दौरान करीब 80 से 100 छात्रों के बाल काटे गए। आरोप है कि जिस समय कटिंग शुरू हुई, कई बच्चे सोने की तैयारी कर रहे थे, जबकि कुछ सो भी चुके थे। ऐसे में रात के समय बच्चों के बाल काटने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

अधीक्षक ने बताई पूरी वजह

आश्रमशाला के अधीक्षक प्रशांत मेश्राम ने कहा कि बच्चों की कटिंग हर दो महीने में की जाती है। बारिश के दिनों में इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। अब गर्मी में बच्चे खेलते हैं और नियमित रूप से बाल नहीं धो पाते, जिससे डैंड्रफ और खुजली की समस्या हो सकती है। इसी वजह से कटिंग शुरू की गई थी। उन्होंने बताया कि शुरूआत में कुछ छात्रों के बाल ट्रिमर से काटे गए थे। बच्चों के इधर-उधर जाने से बचाने के लिए पहले आधी कटिंग की जा रही थी। इसी दौरान ट्रिमर की चार्जिंग खत्म हो गई और नाई ने बाकी कटिंग बाद में करने की बात कही। लेकिन आधे कटे बालों की तस्वीरें वायरल होने के बाद रात में बच्चों के बाल लेवल करने पड़े।

पहले भी बासी भोजन का मामला आया था सामने

इस घटना ने आश्रमशाला की प्रशासनिक व्यवस्था और निगरानी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे पहले इसी आश्रमशाला में छात्रों को बासी भोजन दिए जाने और उनकी तबीयत बिगड़ने का मामला भी सामने आया था। अभिभावकों ने आदिवासी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से आश्रमशाला का दौरा कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही छात्रों के बयान स्वतंत्र रूप से दर्ज करने, बाल काटने में शामिल कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने और निर्णय के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है।

एमपीएससी आंदोलन 48 घंटे का अल्टीमेटम

मांगें पूरी नहीं हुईं तो पुणे बंद या मंत्रालय मार्च की चेतावनी

हिंदमाता नेटवर्क @ पुणे



महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) की परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को पांचवें दिन भी जारी रहा। इस बीच राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार ने राज्य सरकार को 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम दिया है कि वह उनकी मांगों को पूरा करे। इन मांगों में हाल ही में हुए पेपर लीक और पारदर्शिता की कमी के कारण एमपीएससी के चेयरमैन विवेक भीमन्वार को तुरंत पद से हटाना भी शामिल है। रोहित पवार ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो 1,00,000 से अधिक छात्र पुणे की सड़कों पर उतर आएंगे। प्रदर्शनकारी या तो पूरी तरह से पुणे बंद करवाएंगे या फिर सीधे मुंबई में मंत्रालय तक एक बड़ा मार्च निकालेंगे। विरोध प्रदर्शन के पहले दिन से ही उम्मीदवारों के साथ मौजूद रोहित पवार ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 7 या 8 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों से मिलने की उम्मीद है। उस समय पुणे की सड़कों पर हजारों उम्मीदवारों की भारी भीड़ अपनी ताकत दिखाएगी।

पुणे बंद की चेतावनी

उन्होंने कहा कि सीजेपी के अभिजीत दिपके की अपील के बाद पुणे शहर ठप हो सकता है। अब एमपीएससी के उम्मदीदवार और उनके माता-पिता ही फैसला करेंगे। उस समय पुणे के निवासियों को इन छात्रों का समर्थन करना चाहिए। राहुल गांधी के 7 या 8 अक्टूबर को आने की संभावना है। हमारा अनुमान है कि उस दिन पुणे की सड़कों पर लगभग 1,00,000 छात्र होंगे। ये छात्र या तो पुणे बंद का आ'ान करेंगे या सीधे मुंबई में मंत्रालय तक मार्च करेंगे। हम सरकार को दो दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं।

भ्रष्टाचार का आरोप

रोहित पवार ने कहा कि इस आंदोलन की मुख्य वजह परीक्षा बोर्ड में फैला व्यवस्थित भ्रष्टाचार है। उन्होंने एमपीएससी के चेयरमैन विवेक भीमन्वार के तुरंत इस्तीफे की मांग की और कमीशन की भर्ती प्रक्रियाओं की पूरी तरह से ऑडिट और सफाई करने की बात कही।

नितेश राणे की अपील

वहीं, भाजपा नेता और राज्य मंत्री नितेश राणे ने रोहित पवार से अपील की कि वे राजनीतिक फायदे के लिए छात्रों को बंधक न बनाएं। उन्होंने कहा कि यह मामला लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है और दोनों नेताओं को मिलकर रचनात्मक रूप से काम करना चाहिए। साथ ही, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि भविष्य में रोहित पवार उनके साथ कैबिनेट मंत्री के तौर पर बैठ सकते हैं। रोहित पवार को भी बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। वे छात्रों के मुद्दों के लिए लड़ते हैं। उन्हें विरोध करना चाहिए लेकिन छात्रों को बंधक नहीं बनाना चाहिए।

छात्रों के भविष्य का सवाल

मंत्री राणे ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, यह छात्रों के भविष्य का सवाल है। हम छात्रों के भले के लिए मंत्रालय में बैठते हैं। रोहित पवार मेरे दोस्त हैं। कल, वे सरकार में मेरे साथ कैबिनेट मंत्री भी हो सकते हैं। वे अच्छे कामों की तारीफ करने वाले व्यक्ति हैं। हम छात्रों के लिए मिलकर काम करेंगे। वे विरोध जारी रख सकते हैं लेकिन उन्हें छात्रों को बंधक नहीं बनाना चाहिए।

रोहित पवार का पलटवार

मंत्री राणे की इस पेशकश पर रोहित पवार ने इसे राजनीतिक ध्यान भटकाने की कोशिश बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन के खिलाफ बढ़ते जन-आक्रोश से मंत्री घबराए हुए लग रहे हैं। रोहित पवार ने कहा कि मुझे कैबिनेट में जगह देने के बजाय, उन्हें छात्रों के साथ बैठकर उनके मुद्दों का समाधान करना चाहिए। अगर वे हमें सरकार में देखते हैं, तो उन्हें हिम्मत दिखानी चाहिए और अभी विपक्ष में बैठना चाहिए। जब हमारी सरकार आएगी, तब हम मिलकर काम कर सकते हैं।

एससी में मामला जारी तो पैरलल सुनवाई क्यों?

बॉम्बे एचसी का चुनाव आयोग को आदेश देने से इनकार

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई



महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट से एक अहम अपडेट सामने आया है। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि अदालत चुनाव आयोग (ECI) को महाराष्ट्र में मतदाता सूची से नाम न हटाने का कोई भी आदेश जारी नहीं करेगी। उच्च न्यायालय ने 'न्यायिक औचित्य' का पालन करने की बात कहते हुए इस मामले की सुनवाई को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है।

चुनाव आयोग का तर्क : सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला

सुनवाई के दौरान भारतीय चुनाव आयोग का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने अदालत को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही देश भर में एसआईआर से संबंधित व्यापक कानूनी चुनौतियों पर विचार कर रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित उस अंतरिम आदेश का संदर्भ दिया, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों को अपने-अपने राज्यों में एसआईआर की वैधता या उससे संबंधित पहलुओं पर समानांतर सुनवाई करने से रोका गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कुंभकोनी ने पीठ को यह भी सूचित किया कि कई अन्य उच्च न्यायालयों ने भी एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इनमें से कुछ उच्च न्यायालयों ने याचिकाकताओं से कहा है कि वे पहले सुप्रीम कोर्ट से इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि क्या उच्च न्यायालय इन मामलों की सुनवाई कर सकते हैं या नहीं।

चुनाव आयोग का तर्क : सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला

सुनवाई के दौरान भारतीय चुनाव आयोग का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी ने अदालत को बताया कि सर्वोच्च न्यायालय पहले से ही देश भर में एसआईआर से संबंधित व्यापक कानूनी चुनौतियों पर विचार कर रहा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित उस अंतरिम आदेश का संदर्भ दिया, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों को अपने-अपने राज्यों में एसआईआर की वैधता या उससे संबंधित पहलुओं पर समानांतर सुनवाई करने से रोका गया था। वरिष्ठ अधिवक्ता कुंभकोनी ने पीठ को यह भी सूचित किया कि कई अन्य उच्च न्यायालयों ने भी एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। इनमें से कुछ उच्च न्यायालयों ने याचिकाकताओं से कहा है कि वे पहले सुप्रीम कोर्ट से इस बात का स्पष्टीकरण प्राप्त करें कि क्या उच्च न्यायालय इन मामलों की सुनवाई कर सकते हैं या नहीं।

समानांतर सुनवाई की आवश्यकता नहीं : बॉम्बे हाईकोर्ट

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने चुनाव आयोग की दलीलों पर गौर किया। अदालत ने यह स्वीकार किया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश में महाराष्ट्र राज्य का नाम स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं था। इसके बावजूद, पीठ ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्यवाही और इस याचिका का दायरा आपस में जुड़ता है, इसलिए समानांतर सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि जब उच्चतम न्यायालय का अंतरिम रोक आदेश पहले से मौजूद है, तो समानांतर मुकदमेबाजी चलाने का कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होना निर्धारित है।

किसानों को दिवाली की उम्मीद, सरकार देगी अधिक मदद

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई



महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे ने अपने गृह जिले बीड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के किसानों को भरोसा दिलाया कि देवेंद्र फडणवीस सरकार उनकी दिवाली खुशहाल बनाएगी। उन्होंने फसल के नुकसान के बीच किसानों को अधिक मदद के संकेत दिए। मुंडे, बीड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर थीं। जिले की सभी 11 तहसीलों को राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित घोषित किया है। मुंडे ने रविवार को पत्रकारों से कहा कि राज्य सरकार पहले ही 32,000 करोड़ रुपए की फसल ऋण माफी की घोषणा कर चुकी है। पहली बार राज्य सरकार ने किसानों को मुआवजा देने के तय फॉर्मूले से अधिक मुआवजे की घोषणा की है। मुख्यमंत्री फडणवीस किसानों की दिवाली खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सोयाबीन की फसल प्रभावित

मानसून के दौरान कम बारिश होने से सोयाबीन जैसी फसलों की खेती प्रभावित हुई है। किसानों का कहना था कि फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और पैदावार काफी कम रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिनमें ज्यादातर तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करना भी शामिल है।

अभद्र टिप्पणी मामले में महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश नहीं हुए हनी सिंह

मांगा और समय

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई



मशहूर रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हिरदेश सिंह उर्फ यो यो हनी सिंह को महाराष्ट्र साइबर ने सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए। हनी सिंह को एक नोटिस के जरिए व्यक्तिगत रूप से मौजूद होकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था। हालांकि, हनी सिंह की ओर से महाराष्ट्र साइबर से पूछताछ के लिए पेश होने का समय आगे बढ़ाने की मांग की गई है। महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को यह नोटिस एक शिकायत और उसके आधार पर दर्ज मामले की जांच के सिलसिले में भेजा था।

पहले भी जारी हुआ नोटिस

विभाग ने इससे पहले भी उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। बाद में 14 सितंबर को जारी नोटिस में उन्हें 5 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मुंबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में महाराष्ट्र साइबर के कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया था। इस नोटिस को विभाग ने 'फाइनल रिमाइंडर' बताया था।

जांच में सहयोग के निर्देश

मशहूर रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हनी सिंह से जांच में सहयोग करने और मामले से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। नोटिस में कहा गया था कि जांच अधिकारी जरूरत के मुताबिक उनसे दस्तावेज, रिकॉर्ड या अन्य सामग्री मांग सकते हैं। हालांकि, सोमवार को तय समय पर हनी सिंह महाराष्ट्र साइबर के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। उनकी ओर से अब जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। यह मामला हनी सिंह की ओर से एक कॉन्सर्ट के दौरान कथित तौर पर की गई अभद्र टिप्पणी से जुड़ा है। आरोप है कि कॉन्सर्ट के दौरान उनके बयान को लेकर एक व्यक्ति ने महाराष्ट्र साइबर में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की गई और हनी सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया गया।

1 सितंबर को भी नोटिस

इससे पहले 1 सितंबर 2026 को भी हनी सिंह को नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस के जरिए उन्हें जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। महाराष्ट्र साइबर के अनुसार, मशहूर रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर यो यो हनी सिंह तय तारीख और समय पर अधिकारी के सामने उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद विभाग ने 14 सितंबर को दोबारा नोटिस जारी किया था।

अधिकारों का हनन: सपकाल

न्यायमूर्ति भुइयां के बयान का हवाला देकर कांग्रेस नेता ने साधा निशाना

हिंदमाता नेटवर्क @ नागपुर



वोट देने के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की टिप्पणी का हवाला देते हुए, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सोमवार को दावा किया कि देश में संवैधानिक अधिकारों को 'कुचला जा रहा है और उनका अनादर किया जा रहा है'। उनकी यह टिप्पणी जस्टिस भुइयां के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो लाखों भारतीय नागरिकों को मताधिकार से वंचित करती है, वह 'मूल रूप से मनमानी' है और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, जिसे किसी भी तरह की 'दलीलों' से सही नहीं ठहराया जा सकता।

न्यायमूर्ति भुइयां की टिप्पणी

हैदराबाद स्थित 'नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ' में आयोजित एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा कि भारत का संविधान नागरिकों को दो वर्गों में नहीं बांटता, जिनमें से एक वर्ग मताधिकार प्राप्त हो और दूसरा मताधिकार से वंचित हो। इस पर उनकी टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, सपकाल ने कहा कि अब यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है, संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का अनादर किया जा रहा है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ने जो कहा है वह वास्तव में एक तथ्य है।

आम आदमी देश का मालिक

कांग्रेस नेता ने नागपुर हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस देश का मालिक प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि आम आदमी है, जिसके बारे में संविधान स्पष्ट रूप से बताता है। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर (मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण) रूपी जो 'बुलडोजर' चल रहा है, उसका इस्तेमाल निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के अधिकारों, शक्तियों और दलों को बाधित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

निर्वाचन आयोग पर सवाल

समाचारपत्र 'द इंडियन Express की उस खबर के बाद कांग्रेस मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार पर निशाना साध रही है, जिसमें कहा गया था कि निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े फैसलों और आदेशों पर बीते 10 महीनों में कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज कराई थी। अपने दो आयुक्तों द्वारा उठायी गई आपत्तियों को लेकर आलोचनाओं के घेरे में आए निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अलग-अलग विचार और टिप्पणियां किसी भी संस्था में विचार-विमर्श का हिस्सा होती हैं और उसके सभी आदेशों को पूर्ण कानूनी मान्यता प्राप्त है तथा वे स्थापित वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

दोनों आयुक्तों की चिंता सही

सपकाल ने दावा किया कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों द्वारा उठाई गई चिंताएं सही हैं और महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा उठाई गई आपत्तियां भी वैध हैं। उन्होंने कहा, 'अब यह देखना होगा कि (केंद्रीय गृह मंत्री) अमित शाह और प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) में कोई नैतिकता बची है या नहीं।' केरलम सरकार द्वारा 2006 की एक सड़क निर्माण परियोजना में सतर्कता जांच के आदेश दिए जाने पर, जब ज्ञानेश कुमार राज्य में पीडब्ल्यूडी सचिव थे, सपकाल ने दावा किया कि यह साबित हो गया है कि 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वोट चोर हैं'। कांग्रेस नेता ने कहा कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने (छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से) इस्तीफा दिया, ज्ञानेश कुमार को भी इस्तीफा देना होगा।

राकांपा ने एसआईआर का समर्थन किया

न्यायमूर्ति भुइयां की टिप्पणी का हवाला देकर मताधिकार से वंचित करने पर जताई आपत्ति

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई



शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की आलोचनात्मक टिप्पणियों का समर्थन किया। भुइयां ने रविवार को हैदराबाद के नलसार विश्वविद्यालय में कहा कि लाखों भारतीय नागरिकों को उनके मताधिकार से 'वंचित' करने वाली कोई भी प्रक्रिया 'मूल रूप से मनमानी' और संवैधानिक व्यवस्था के 'खिलाफ' है।

मताधिकार के अधिकार का सवाल

टिप्पणियों का समर्थन करते हुए राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि लाखों लोगों को मनमाने ढंग से मताधिकार से वंचित करना नागरिकों के मतदान के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। क्रास्टो ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की दलीलें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भारत निर्वाचन आयोग के कथित गलत कामों को छिपाने की कोशिश का संकेत थीं।

संविधान और लोकतंत्र का हवाला

क्रास्टो ने बताया, 'एसआईआर मुद्दे पर न्यायमूर्ति भुइयां का बयान हमारे संविधान और लोकतंत्र को कायम रखता है। मतदाताओं को मनमाने ढंग से मताधिकार से वंचित करना उनके मतदान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।'न्यायमूर्ति भुइयां ने 'नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ' में आयोजित 19वीं न्यायमूर्ति बोध राज साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में कहा कि भारत का संविधान नागरिकों को दो वर्गों में नहीं बांटता, जिनमें से एक वर्ग मताधिकार प्राप्त हो और दूसरा मताधिकार से वंचित हो।

अनुच्छेद 326 और 14 का उल्लेख

उन्होंने कहा कि व्यापक पैमाने पर भारतीय नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 और 14 का सीधा उल्लंघन होगी।

एसआईआर को लेकर विरोध

विपक्षी दल और कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा), साथ ही नागरिक संस्थाएं कथित तौर पर एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया सभी कानूनों और संवैधानिक मानदंडों का पालन करते हुए की जा रही है।

दुकान में घुसाई बाइक

मालिक और बेटे को जान से मारने की धमकी

हिंदमाता नेटवर्क @ लातूर



लातूर शहर में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी मोटरसाइकिल एक खानपान की दुकान में घुसा दी और दुकान बंद नहीं करने पर उसके मालिक तथा उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। घटना शनिवार देर रात अंबाजोगाई रोड पर हुई।

दुकान का सामान क्षतिग्रस्त

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि शिकायतकर्ता चीनी खानपान की दुकान चलाता है। उसके अनुसार, आरोपी स्थानीय निवासी है जिसने कथित तौर पर अपनी मोटरसाइकिल दुकान में घुसा दी और वहां का काउंटर, ठेला, रेफ्रिजरेटर तथा अन्य सामान क्षतिग्रस्त कर दिया। अधिकारी ने घटना के पीछे की वजह के बारे में विस्तार से नहीं बताया।

आरोपी पर मामला दर्ज

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर दुकान के मालिक और उसके बेटे को गाली दी तथा दुकान बंद नहीं करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर रविवार को आरोपी के खिलाफ गैर-संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज की गई।

मुंबई-बेंगलुरु स्लीपर वंदे भारत में 11 स्टॉपेज

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई

मुंबई से बेंगलुरु की दूरी अब केवल 16 घंटों में पूरी की जा सकेगी। रेलवे बोर्ड ने मुंबई-बेंगलुरु स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्तावित रूट और टाइम टेबल जारी कर दिया है, जिसके तहत यह हाई स्पीड ट्रेन कुल 11 स्टेशनों पर ठहराव के साथ दौड़ेगी। बोर्ड द्वारा तय किए गए इस नए रूट से पश्चिम महाराष्ट्र और उत्तर कर्नाटक के प्रमुख शहरों का पत्ता कट गया है, जिससे एक तरफ सोलापुर रूट के यात्रियों में उत्साह है तो दूसरी तरफ मिरज, कोल्हापुर और बेलगावी क्षेत्र के लोगों में निराशा देखी जा रही है।

ट्रेन पुणे और सोलापुर होकर गुजरेगी

मुंबई और बेंगलुरु के बीच जल्द शुरू होने वाली देश की अत्याधुनिक स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रस्तावित रूट और समय सारणी सामने आ चुकी है। रेलवे बोर्ड के नए प्लान के अनुसार यह ट्रेन पुणे और सोलापुर होकर गुजरेगी। यह हाई स्पीड ट्रेन 1,137 किलोमीटर की दूरी महज 15 से 16 घंटे में तय करेगी। यह गाड़ी सीएसएमटी मुंबई से चलकर कल्याण, पुणे, सोलापुर, कलबुर्गी, वाडी, रायचूर, गुंतकल, अनंतपुर, धर्मावरम होते हुए केएसआर बेंगलुरु पहुंचेगी।

हिंदमाता एंकर: 2,353 करोड़ की परियोजनाओं में देरी

मुंबई लोकल के भिवपुरी-वाणगांव कारशेड 7 साल बाद भी अधूरे

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई



मुंबई उपनगरीय नेटवर्क में लोकल ट्रेनों के बढ़ते बेड़े के उचित रखरखाव और मौजूदा शेडस का बोझ घटाने के लिए प्रस्तावित भिवपुरी व वाणगांव कारशेड परियोजनाएं 7 साल बीत जाने के बाद भी अधूरी पड़ी हैं। मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन द्वारा वर्ष 2019 में मंजूर किए गए इन प्रोजेक्ट्स को भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और प्रशासनिक सुस्ती के कारण भारी देरी का सामना करना पड़ा है। एमयूटीपी 3 ए के तहत 2,353 करोड़ रुपए की लागत वाले इन दोनों कारशेड का संचालन समय पर शुरू न होने से के आगामी उपनगरीय मार्गों की सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका गहरा गई है। पनवेल-कर्जत उपनगरीय कॉरिडोर के लिए अहम भिवपुरी कारशेड को लेकर 45.24 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित होने के बावजूद निर्माण का मुख्य ठेका छह साल बाद अगस्त 2025 में दिया गया।

2027 की सेवाओं पर असर संभव

वर्तमान में वहां केवल मिट्टी भराई और सुरक्षा दीवार का प्राथमिक कार्य चल रहा है, जबकि निरीक्षण शेड, वॉशिंग लाइन और पुलों के नक्शों की तकनीकी मंजूरी अभी बाकी है। साल 2027 तक पनवेल-कर्जत मार्ग शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन तब तक भिवपुरी कारशेड तैयार होना मुश्किल दिखता है, जिससे लोकल के मेंटेनेंस का अतिरिक्त भार अन्य शे पर पड़ेगा।

वसई रोड टर्मिनस का काम तेज

मुंबई से सटे वसई-विरार और पालघर क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण वसई रोड रेलवे टर्मिनस परियोजना अब क्रियान्वयन चरण में पहुंच गई है। पश्चिम रेलवे ने परियोजना के प्रमुख ठेके दे दिए हैं और निर्माण कार्य तेजी से जारी है, करीब 150.25 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को मार्च 2028 तक पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा गया है।

43.68 हेक्टेयर जमीन की जरूरत

दूसरी ओर विरार-डहाणू चौहरीकरण से जुड़े वाणगांव कारशेड के लिए 43.68 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमे बड़ा हिस्सा वन भूमि का है। इस परियोजना को फरवरी 2026 में पहले चरण की सैद्धांतिक वन मंजूरी तो मिल गई, लेकिन दूसरे चरण की अंतिम पर्यावरण मंजूरी अब भी अटकी हुई है। नतीजतन, वहां अब तक जमीनी काम शुरू नहीं हो सका है। सूत्रों के मुताबिक मध्य रेल के कुर्ला, कलवा, सानपाड़ा और पश्चिम रेल के मुंबई सेंट्रल, कांदिवली व विरार कारशे पर दबाव कम करने के उद्देश्य से शुरू हुई यह योजना अब भी फाइलों और बुनियादी अड़चनों में उलझी हुई है। एमआरवीसी का दावा है कि तकनीकी मंजूरियों के साथ काम को गति दी जा रही है, परंतु वास्तविक संचालन शुरू होने में अभी लंबा वक्त लगेगा।

मुंबई में ट्रैफिक जाम का समाधान

बांद्रा-वसोर्वा सी लिंक से जुड़ेगा गोरेगांव एलिवेटेड रोड

हिंदमाता संवाददाता @ मुंबई



मुंबईकरों को रोजमर्रा के भीषण ट्रैफिक जाम से स्थायी मुक्ति दिलाने और सफर का समय घटाने के लिए बीएमसी और एमएसआरडीसी ने एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम तेज कर दिया है। बांद्रा से गोरेगांव बांगुर नगर के सफर को सुगम बनाने के लिए समुद्री सेतु और एलिवेटेड मार्गों का मजबूत नेटवर्क का जाल बिछाया जाएगा। वर्ष 2028 के अंत तक इन दोनों अहम परियोजनाओं के पूरा होते ही साल 2029 से पश्चिम उपनगर का सफर बेहद तेज और आरामदायक हो जाएगा। साथ ही बांद्रा से गोरेगांव के बीच की दूरी महज 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी। उत्तरी मुंबई तटीय सड़क परियोजना के तहत बीएमसी वसोर्वा से दहिसर-भायंदर के बीच कोस्टल रोड बना रही है।

जाम से मिलेगी राहत

वसोर्वा इंटरचेंज से गोरेगांव बांगुर नगर तक 4.54 किलोमीटर लंबा आठ लेन का एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है। 45 मीटर चौड़े इस पुल के लिए पिलर सखड़े करने का काम तेजी से चल रहा है। हाल ही में मनपा के अतिरिक्त आयुक्त अभिजीत बांगर ने मौके का मुआयना कर काम को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

प्रोजेक्ट 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य

इस एलिवेटेड रोड को एमएसआरडीसी के 17 किलोमीटर लंबे बांद्रा-वसोर्वा सी लिंक से सीधे जोड़ा जाएगा, जो आगे बांद्रा-वर्ली सी लिक से जुड़ेगा। प्रोजेक्ट को दिसंबर 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लिक रोड और एसवी रोड के भारी जाम के कारण वसोर्वा से गोरेगांव जाने में 40 से 50 मिनट का समय बर्बाद होता है।

विचार प्रवाह



महत्त्वाकांक्षा वो नहीं है जो इंसान करना चाहता है, बल्कि वो है जो इंसान करता है, क्योंकि बिना कर्म के महत्त्वाकांक्षा बस एक कल्पना है।
- ब्रायंट एच. मैकगिल

संपादकीय

एशियाई खेलों से मिली सीख

एशियाई खेलों में भारत का चौथे स्थान पर रहना निश्चित रूप से संतोष का विषय है। भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 85 पदक जीते, जिनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। आइची-नागोया में संपन्न इन खेलों के अंतिम दिनों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदकों की संख्या बढ़ाई। यह उपलब्धि बताती है कि भारत एशिया की शीर्ष चार खेल शक्तियों में अपनी जगह बना चुका है। लेकिन इस सफलता के साथ एक बड़ा सवाल भी सामने खड़ा है कि चीन और जापान जैसी खेल महाशक्तियों के मुकाबले भारत अभी कहां खड़ा है और आने वाले दशकों में ओलंपिक की दावेदारी में उसकी स्थिति क्या होगी? इस बार के एशियाई खेलों की कुछ उपलब्धियां विशेष रूप से उत्साह बढ़ाने वाली हैं। तीरंदाजी में भारत ने नौ पदक जीते, जिनमें पांच स्वर्ण शामिल हैं। कुमकुम मोहोद ने रिकर्व कैटेगरी में भारत की पहली व्यक्तिगत उपलब्धि हासिल कर इतिहास रचा। बॉक्सिंग में तीन और कुश्ती में दो स्वर्ण पदक भी भारतीय खिलाड़ियों की क्षमता को दशार्ते हैं। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। क्रिकेट, हॉकी और कबड्डी में भी भारत ने अपना वर्चस्व कायम रखा। महिला हॉकी टीम की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। भारतीय खिलाड़ियों ने अनुशासन, आत्मविश्वास और ऊंचे मनोबल के साथ शानदार प्रदर्शन किया। मौजूदा चैंपियन चीन को हराकर महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक का 44 साल पुराना इंतजार खत्म किया। ऐसी उपलब्धियां केवल पदक नहीं, बल्कि देश में खेल संस्कृति को मजबूत करने वाली प्रेरणा भी हैं। हालांकि, हर क्षेत्र में प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं रहा। एथलेटिक्स में भारत को निराशा हाथ लगी। महिलाओं की 4७400 मीटर रिले में मिला एकमात्र स्वर्ण ही इस क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि रही। निशानेबाजी में भी प्रदर्शन उत्साहजनक नहीं रहा। पिछले ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर का इस बार खाली हाथ लौटना भी निराशाजनक रहा। इन कमजोरियों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। चीन में हुए पिछले एशियाई खेलों से तुलना करें तो इस बार भारत का प्रदर्शन कुछ फीका रहा। पिछली बार भारत ने 28 स्वर्ण सहित कुल 106 पदक जीते थे। इस बार सात स्वर्ण कम हुए और कुल पदकों की संख्या भी 21 घट गई। यह अंतर खेल नीति-निमार्ताओं के लिए चेतावनी है। केवल कुछ खिलाड़ियों की असाधारण सफलता को देश के खेल विकास का पैमाना नहीं माना जा सकता। नागोया की उपलब्धियों का जश्न मनाना जरूरी है, लेकिन इसके साथ आत्ममंथन भी होना चाहिए। ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रतिभाओं की पहचान बहुत पहले से करनी होगी। खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं, वैज्ञानिक तकनीक, बेहतर कोचिंग और मानसिक मजबूती देने वाली व्यवस्था उपलब्ध करानी होगी। साथ ही चोट से बचाव, पोषण और खेल विज्ञान से जुड़े मजबूत सपोर्ट सिस्टम पर भी ध्यान देना होगा। एशियाई खेलों ने भारत को सफलता के साथ उसकी कमजोरियों का आईना भी दिखाया है। अब लक्ष्य केवल एशिया में शीर्ष चार में बने रहना नहीं, बल्कि चीन, जापान जैसी शक्तियों के अंतर को कम करना होना चाहिए। वर्ष 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारी का समय अभी से शुरू करना होगा। नागोया की उपलब्धियां उत्साह दें और कमियां सुधार की प्रेरणा बनें, तभी भारत विश्व खेल मंच पर अपनी वास्तविक क्षमता के अनुरूप स्थान हासिल कर सकेगा।

आज का इतिहास



■ 1499 - फ्रांस के राजा लुईस ने मिलान पर कब्जा किया।
■ 1723 - बेंजामिन फ्रेंकलिन 17 साल की उम्र में फिलाडेल्फिया पहुंचे।
■ 1762 - ब्रिटिश सैनिकों ने फिलीपींस के मनीला पर कब्जा किया।
■ 1862 - भारतीय दंड संहिता कानून पारित हुआ और एक जनवरी से लागू हुआ।
■ 1919 - तांबुलीस्की बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बने।
■ 1935 - भारत में 32 साल के सबसे लंबे समय तक अंपायरिंग करने वाले जीवन डी घोष का बंगाल में जन्म हुआ।
■ 1957 - सोवियत संघ ने नोवाया जेमल्या में परमाणु परीक्षण किया।
■ 1972 - मेक्सिको में ट्रेन पटरी से उतरने से 208 लोगों की मौत।
■ 1980 - गुयाना ने संविधान को अंगीकार किया।
■ 1981 - काहिरा में सैनिक परेड के दौरान एक सैनिक समूह द्वारा मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या।
■ 1983 - पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
■ 1987 - फिजी एक गणराज्य घोषित हुआ।
■ 1994 - यूनेस्को ने वर्ष 1995 को संयुक्त राष्ट्र सहिष्णुता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की।
■ 1995 - दो स्विस वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के सौर व्यवस्था के बाहर गृह की पहली बार पहचान की।
■ 1999 - संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन आस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में प्रारम्भ।
■ 2000 - इस्त्रायली पुलिस द्वारा अलअक्सा मस्जिद में जबरन प्रवेश के बाद हिंसा शुरू, यूगोस्लाविया में रक्तहीन जनक्रान्ति के बीच राष्ट्रपति मिलोसेविच देश छोड़कर भागे, विपक्षी नेता कोस्तुनिका ने स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किया।
■ 2002-नेपाल के नरेश ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव ने सत्ता नहीं संभालने की घोषणा की।
■ 2004-इस्त्रायली सैन्य अभियान को रोकने का प्रस्ताव अमेरिका ने वीटो किया। अल्खानोव चेचेन्या के राष्ट्रपति बने।
■ 2006 - संयुक्त राष्ट्र ने लेबनान में शांति रक्षकों को बल प्रयोग का अधिकार दिया।
■ 2007 -परवेज मुशर्रफ एकतरफा जीत के साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित घोषित हुए। कोरू में एरियन-5 रॉकेट के सहारे आस्ट्रेलियाई-अमेरिकी टेलीविजन उपग्रह का परीक्षण किया गया। बाबा साहेब भोसले - प्रसिद्ध भारतीय वकील, नेता एवं महाराष्ट्र के आठवें मुख्यमंत्री।
■ 2008 - वैश्विक मंदी के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के नकद सुरक्षित अनुपात (सीआरआर) में आधा प्रतिशत की कटौती का फैसला किया।
■ 1893 - मेघनाथ साहा - गणित व भौतिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक।
■ 1946 - विनोद खन्ना, हिन्दी फि ल्म अभिनेता।
■ 1963-ग्रैंड ओल्ड मैन बाबा खड़क सिंह-पंजाब के स्वतंत्रता सेनानी।

एफडीए में सुधार की असली परीक्षा

मुंढे की कार्रवाई से उम्मीद

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई



उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राऊत ने महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे को पत्र देकर विभाग के कुछ अधिकारियों पर कथित वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर, मुंढे ने इन आरोपों के समर्थन में ठोस जानकारी और प्रमाण सामने रखने को कहा है तथा कहा है कि आरोप सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे विवाद के बीच एक सकारात्मक पहलू यह है कि मुंढे के नेतृत्व में मिलावट और खाद्य सुरक्षा के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। इससे आम लोगों को यह अहसास हुआ है कि खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन गंभीर हो सकता है। हाल के दिनों में एफडीए की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त किए जाने की खबरें भी सामने आई हैं।

भरोसा बढ़ाने का अवसर

खाद्य पदार्थों में मिलावट का सवाल सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा है। दूध, पनीर, मिठाई, तेल या अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट केवल उपभोक्ता के साथ धोखा नहीं, बल्कि उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए एफडीए की सख्त कार्रवाई का असर केवल कुछ दुकानों या प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रहता। इससे बाजार में नियमों का भय और उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा होती है। यही कारण है कि मौजूदा कार्रवाई ने विभाग के सामने अपनी सार्वजनिक छवि सुधारने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी रखा है।

पुरानी रिपोर्ट से सबक

कुछ वर्ष पहले एफडीए में कथित भ्रष्टाचार और विभागीय खामियों को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई थी। उस समय महेश झगड़े, अधिवक्ता उदय बोपशेट्टी और संजय काले की समिति गठित की गई थी। समिति ने विभाग की कार्यप्रणाली और उसमें मौजूद कमजोरियों पर गंभीरता से विचार किया था। लंबे समय तक कुछ अधिकारियों का विशेष शहरों में टिके रहना और पोस्टिंग को लेकर उठने वाले सवाल भी उस दौर में चर्चा में रहे। बाद में महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण के तत्कालीन प्रमुख न्यायमूर्ति अंबादास जोशी ने भी इस रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने की कोशिश की थी। सवाल यह है कि उन पुराने अनुभवों से विभाग ने कितना सबक लिया?

मनुष्यबल की कमी

ट्रांसपोर्ट और एफडीए जैसे विभाग लंबे समय से कम मनुष्यबल में काम कर रहे हैं। यह स्थिति प्रशासन की क्षमता को प्रभावित करती है। एफडीए का दायरा बहुत व्यापक है और खाद्य पदार्थों से लेकर दवाओं तक उसकी जिम्मेदारी जनता के स्वास्थ्य से जुड़ी है। ऐसे में पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारी न होने पर निगरानी और कार्रवाई दोनों प्रभावित होना स्वाभाविक है। इससे भी गंभीर प्रश्न यह है कि नई भर्तियों की प्रक्रिया बार-बार विवादों में क्यों आती है।

भर्ती प्रक्रिया पर सवाल

ड्रग इंस्पेक्टर के पदों पर एमपीएससी के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों के बाद प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए। रिपोर्टों के अनुसार, 154 पदों के लिए चयन प्रक्रिया में 488 उम्मीदवारों की अस्थायी सूची बनी थी और पुलिस जांच के कारण अंतिम चयन रोक दिया गया। एमपीएससी ने प्रश्नपत्र लीक होने के आरोपों की जांच पुलिस को सौंपने की बात कही थी। यदि विभाग में नए और योग्य अधिकारी समय पर आते हैं तो इससे निगरानी व्यवस्था मजबूत हो सकती है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाना बेहद जरूरी है।

आरोपों की जांच जरूरी

संजय राऊत ने आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी होटल, रेस्तरां और अन्य कारोबारियों पर लाइसेंस निलंबन का दबाव बनाकर पैसे मांगते हैं और कथित तौर पर पहले की तुलना में अधिक रकम वसूली जा रही है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में आरोप लगाने के साथ प्रमाण सामने लाना भी जरूरी है। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ ठोस सबूत हैं तो उन्हें एसीबी या संबंधित जांच एजेंसी के सामने रखा जाना चाहिए। यही विपक्ष की रचनात्मक भूमिका भी हो सकती है—सिर्फ आरोप नहीं, बल्कि प्रमाण और जवाबदेही की मांग।

सवाल व्यवस्था पर भी

मुद्दा केवल यह नहीं होना चाहिए कि कौन अधिकारी कितना पैसा लेता है। असली सवाल यह भी है कि कितने पद खाली हैं? वे वर्षों से खाली क्यों हैं? कौन अधिकारी लंबे समय से एक ही शहर में तैनात है? स्थानांतरण की नीति कितनी पारदर्शी है? अनुशासनात्मक कार्रवाई की फाइलें कितने समय तक मंत्रालय में अटकती हैं? यदि किसी अधिकारी के खिलाफ गंभीर शिकायत या जांच है तो उसका निपटारा समय पर होना चाहिए। व्यवस्था ऐसी हो कि ईमानदार अधिकारी को काम करने में परेशानी न हो और भ्रष्टाचार करने वाले को संरक्षण न मिले।

एफडीए का असर व्यापक

एफडीए को केवल कानून लागू करने वाला विभाग समझना बड़ी भूल होगी। इसका सीधा संबंध किसानों, उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य व्यवस्था से है। दूध में मिलावट रुकती है तो शुद्ध दूध की मांग बढ़ सकती है और उसका लाभ दूध उत्पादक किसानों को मिल सकता है। दूसरी ओर मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण लोग बीमार पड़ते हैं तो परिवारों का आर्थिक बोझ बढ़ता है और स्वास्थ्य व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इसलिए एफडीए की प्रभावी कार्यप्रणाली का असर खेत से लेकर रसोई और अस्पताल तक दिखाई देता है।

अब बदलाव स्थायी हो

आज उपभोक्ता पहले से अधिक जागरूक हो रहा है। फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैकेट पर लिखी समाप्ति तिथि और घर में आने वाले दूध की शुद्धता को लेकर लोगों में सावधानी बढ़ी है। एफडीए की कार्रवाई ने इस जागरूकता को गति दी है। महाराष्ट्र में हो रही सख्त कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हुई है। मुंढे के नेतृत्व में विभाग की सक्रियता के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार के सामने अब इस व्यवस्था को संस्थागत और स्थायी बनाने की चुनौती है।

सुधार ही असली कसौटी

किसी एक अधिकारी की सक्रियता से व्यवस्था में अस्थायी बदलाव तो संभव है, लेकिन स्थायी सुधार के लिए पूरी प्रणाली को बदलना होगा। एफडीए में पर्याप्त मनुष्यबल, पारदर्शी भर्ती, अधिकारियों के नियमित स्थानांतरण, भ्रष्टाचार की शिकायतों की स्वतंत्र जांच और लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई का समयबद्ध निपटारा जरूरी है। आरोप सही हैं तो कार्रवाई हो और गलत हैं तो उन्हें प्रमाण के अभाव में आगे न बढ़ाया जाए। जनता को शुद्ध भोजन और सुरक्षित दवाएं उपलब्ध कराना सरकार की मूल जिम्मेदारी है। इसलिए एफडीए में चल रही मौजूदा सख्ती को किसी व्यक्ति विशेष की कार्यशैली तक सीमित रखने के बजाय इसे ऐसी मजबूत व्यवस्था में बदलना होगा, जो अधिकारी बदलने के बाद भी उतनी ही प्रभावी रहे। यही महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन की वास्तविक परीक्षा होगी।

डिजिटल युग में 'डम्ब फोन' की वापसी

● स्मार्टफोन के बढ़ते दबाव के बीच सादगी, गोपनीयता और मानसिक शांति की तलाश

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली



किसी पुरानी सीरियल या फिल्म को देखते हुए जब लैंडलाइन फोन पर बात करते और स्मार्टफोन के बिना जीवन जीते लोग दिखाई देते हैं तो वह दौर आज के समय में बेहद सरल और शांत नजर आता है। आज 60 वर्ष की उम्र पार कर चुके अनेक लोगों ने उस जीवन को वास्तव में जिया है। तब फोन संवाद का माध्यम था, जिंदगी का केंद्र नहीं। इसके बाद स्मार्टफोन और तेज तकनीकी विकास ने हमारे जीवन को चारों ओर से घेर लिया। आज फोन हमारे व्यक्तित्व और दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यहां तक कि हमारे कई फैसलों पर भी एल्गोरिद्म का प्रभाव पड़ने लगा है।

डिजिटल जीवन का बढ़ता तनाव

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव के बीच डिजिटल दुनिया तेजी से विस्तार कर रही है। लेकिन इसके साथ ही उसके तनाव भी सामने आने लगे हैं। घंटों तक खत्म न होने वाली स्क्रॉलिंग, लगातार ध्यान खींचने वाले ऐप, निजी जानकारी के इस्तेमाल की चिंता और यह एहसास कि हमारा फोन हर समय हमारी गतिविधियों पर नजर रख रहा है, लोगों को परेशान करने लगा है। लगातार जुड़े रहने की मजबूरी ने सुविधा को कई बार मानसिक दबाव में बदल दिया है। ऐसे में डिजिटल दुनिया में पैदा हो रही दरारों के बीच लोगों को फिर से सरल और सीमित तकनीकी जीवन की जरूरत महसूस होने लगी है।

'डम्ब फोन' की वापसी

इसी बदलाव का सबसे स्पष्ट संकेत 'डम्ब फोन' यानी सीमित सुविधाओं वाले साधारण मोबाइल फोन की बढ़ती लोकप्रियता है। दुनिया के कई हिस्सों में इसकी मांग फिर बढ़ रही है। खासकर डिजिटल थकान महसूस कर रहे शहरी इलाकों के युवा, जेन जी और मिलेनियल पीढ़ी के लोग इन फोन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। स्मार्टफोन आने के बाद डम्ब फोन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। छोटे शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में इसका इस्तेमाल जारी रहा। कम कीमत, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, मजबूत बनावट और कॉल तथा एसएमएस जैसी बुनियादी सुविधाएं इसकी सबसे बड़ी ताकत रही हैं।

डिजिटल डिटॉक्स की चाह

शहरों में डम्ब फोन की बढ़ती मांग के पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण डिजिटल डिटॉक्स की इच्छा है। लोग अपना समय और ध्यान फिर से अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। लगातार ऑनलाइन रहने की बेचैनी से छुटकारा पाने और मानसिक शांति हासिल करने के लिए कुछ लोग जानबूझकर स्मार्टफोन से दूरी बना रहे हैं। यह बदलाव तकनीक का पूरी तरह विरोध नहीं है, बल्कि यह तय करने की कोशिश है कि तकनीक का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक हो और वह व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित न करने लगे।

निजता भी बड़ा मुद्दा

डिजिटल दुनिया में निजी जानकारी की सुरक्षा भी गंभीर चिंता बन गई है। स्मार्टफोन में मौजूद विभिन्न ऐप उपयोगकर्ता की पसंद, गतिविधियों और ऑनलाइन व्यवहार से जुड़ी जानकारियां जुटाते हैं। ऐसे में अपना डिजिटल फुटप्रिंट कम करने की इच्छा भी बढ़ रही है। डम्ब फोन में अत्यधिक ऐप और लगातार सक्रिय डिजिटल सेवाएं नहीं होतीं। इससे उपयोगकर्ता को अपने समय और तकनीकी गतिविधियों पर अपेक्षाकृत अधिक नियंत्रण मिलता है। आने वाले समय में निजी डेटा की सुरक्षा का सवाल जितना महत्वपूर्ण होगा, उतना ही यह रुझान भी मजबूत हो सकता है।

लैंडलाइन की भी दस्तक

डम्ब फोन के साथ ही कुछ जगहों पर कभी पुराना हो चुका लैंडलाइन फोन भी फिर इस्तेमाल में आता दिखाई दे रहा है। इसके पीछे भी लगभग वही कारण हैं। लोग आमने-सामने या सीधे मन से संवाद करना चाहते हैं और हर समय ऑनलाइन रहने की मजबूरी से बाहर निकलना चाहते हैं। वर्तमान क्षण को पूरी तरह जीने की इच्छा भी इस बदलाव को बढ़ावा दे रही है। इसलिए इसे केवल पुरानी वस्तुओं की वापसी मानना उचित नहीं होगा। यह डिजिटल जीवनशैली के अतिरेक के खिलाफ एक शांत प्रतिक्रिया भी है।

बाजार ने भी बदली दिशा

बाजार और मोबाइल कंपनियां भी इस बढ़ते रुझान को समझ रही हैं। अब ऐसे डम्ब फोन तैयार किए जा रहे हैं जिनमें जरूरत के मुताबिक व्हाट्सऐप, यूपीआई और वीडियो कॉलिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। यानी कंपनियां उपभोक्ताओं को पूरी तरह डिजिटल दुनिया से बाहर निकालने के बजाय सीमित और आवश्यक तकनीक उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2026 तक भारत में करीब 22 करोड़ लोगों ने डम्ब फोन की ओर रुख करना शुरू किया है। 2024 में इस बाजार का मूल्य लगभग 2.3 अरब डॉलर था और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।

केवल पुरानी यादों का मामला नहीं

पहले डम्ब फोन, लैंडलाइन, डायरी लिखने या पुराने दौर के शौक अपनाने को जेन जी और मिलेनियल पीढ़ी के 'नॉस्टैल्जिया' यानी पुराने समय की याद से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। यह केवल अतीत की ओर लौटने की इच्छा नहीं है। इसके पीछे डिजिटल जीवन के तनाव के खिलाफ एक मौन विरोध भी है। लोग अपना समय, ध्यान, निजता और मानसिक शांति फिर हासिल करना चाहते हैं। यह इस बात का संकेत है कि आधुनिकता का अर्थ केवल अधिक से अधिक तकनीक अपनाना नहीं हो सकता।

तकनीक पर नियंत्रण जरूरी

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार के साथ आने वाले वर्षों में तकनीक हमारे जीवन में और गहराई से प्रवेश करेगी। ऐसे में डम्ब फोन की बढ़ती लोकप्रियता को तकनीक विरोधी अभियान के रूप में देखना उचित नहीं होगा। यह इस बात का संकेत है कि लोग तकनीक की सीमाएं स्वयं तय करना चाहते हैं। सवाल यह नहीं है कि स्मार्टफोन रहेगा या डम्ब फोन, बल्कि असली सवाल यह है कि हमारे जीवन को नियंत्रित कौन करेगा—हम तकनीक को या तकनीक हमें। तकनीक का उद्देश्य जीवन को सरल बनाना होना चाहिए, न कि व्यक्ति को उसकी गिरफ्त में लेना।

प्रेरक प्रसंग

मूर्ख मित्र



किसी राज्य में एक राजा का शासन था। उसके राजमहल में एक बंदर सेवक के रूप में रहता था। वह बंदर राजा का बहुत विश्वासपात्र था। वह हमेशा राजा की सेवा में तत्पर रहता और राजा भी उस पर बहुत भरोसा करता था। अपने विश्वास के कारण राजा ने उसे इतनी स्वतंत्रता दे रखी थी कि वह अंत:पुर में भी बिना किसी रोक-टोक के आ-जा सकता था। बंदर राजा का सच्चा भक्त था, लेकिन वह बहुत मूर्ख था। उसे अपने कार्यों के परिणाम के बारे में सोचने की आदत नहीं थी। राजा के प्रति उसका प्रेम सच्चा था, लेकिन उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन राजा अपने कक्ष में आराम से सो रहा था। बंदर उसके पास बैठकर पंखा झल रहा था। तभी उसने देखा कि एक मक्खी बार-बार उड़कर राजा की छाती पर बैठ रही है। बंदर ने पंखे से मक्खी को हटाने की कोशिश की। मक्खी उड़ जाती, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर राजा की छाती पर आकर बैठ जाती। बंदर को मक्खी पर बहुत क्रोध आया। उसने सोचा कि यह छोटी-सी मक्खी बार-बार मेरे स्वामी को परेशान कर रही है। अब इसे किसी भी तरह सबक सिखाना चाहिए। क्रोध में आकर बंदर ने पंखा एक तरफ रख दिया और राजा की तलवार उठा ली। उसने मन में निश्चय किया कि जैसे ही मक्खी दोबारा राजा की छाती पर बैठेगी, वह एक ही वार में उसे मार देगा। कुछ ही देर बाद मक्खी फिर उड़कर राजा की छाती पर आ बैठी।

■ बंदर ने बिना सोचे-विचारे पूरी ताकत से तलवार चला दी। मक्खी तो तुरंत उड़ गई, लेकिन तलवार का वार राजा की छाती पर लगा। राजा गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ ही समय में उसकी मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु से पूरे महल में शोक छा गया। बंदर अपनी गलती समझने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता था।

■ उसकी मूर्खता और बिना सोचे किए गए काम ने उसके प्रिय स्वामी की जान ले ली। इस घटना से यह शिक्षा मिलती है कि केवल प्रेम और निष्ठा पर्याप्त नहीं हैं, बुद्धि और विवेक भी आवश्यक हैं। बिना सोचे-समझे किया गया कार्य कभी-कभी बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। सीख: मूर्ख मित्र की अपेक्षा विद्वान शत्रु अधिक अच्छा होता है।

राशिफल

मेष- नौकरी में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा। व्यापार में लाभ की गति थोड़ी धीमी रह सकती है। परिवार में बड़ों के आशीर्वाद से रुके काम बनेंगे। आर्थिक संतुलन बनाए रखें, बजट के अनुसार चलें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सुबह टहलना शुरू करें।

वृषभ-कार्यस्थल पर नई योजनाएं बनाने के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में साझेदारी से बड़ा लाभ मिल सकता है। प्रेम जीवन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा। आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। सेहत में सुधार होगा, चुस्ती-फुर्ती रहेगी।

मिथुन-कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर लाभ कमाएंगे। परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा। अचानक रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

कर्क-कार्यक्षेत्र में आपकी एकाग्रता से परिणाम अच्छे आएंगे। व्यापार में दूरगामी सोच से मुनाफा कमा सकते हैं। संतान के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी, हल्का सुपाच्य भोजन लें।

सिंह- कार्यस्थल पर वाद-विवाद से दूर रहना ही समझदारी है। व्यापारिक सौदों में जल्दबाजी न करें, समीक्षा करें। घर में छोटी बातों पर तूल न दें, शांति रखें। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना जरूरी होगा। थकान और सुस्ती दूर करने के लिए आराम लें।

कन्या- आपकी कूटनीति से कार्यस्थल की बाधाएं दूर होंगी। व्यापार में नए ऑर्डर या अनुबंध मिलने के संकेत हैं। भाई-बहनों से संबंध मधुर और मजबूत होंगे। वित्तीय लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति महसूस होगी।

तुला-कार्यक्षेत्र में आपकी बोली और व्यवहार की प्रशंसा होगी। व्यापार में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे, मुनाफा बढ़ेगा। परिवार में हंसी-खुशी का माहौल बना रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, बचत बढ़ेगी। सेहत अच्छी रहेगी, दिन तनावमुक्त बीतेगा।

वृश्चिक- कार्यस्थल पर आपकी नई सोच को स्वीकार किया जाएगा। व्यापार में विस्तार के योग हैं, प्रयास तेज करें। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता और मिठास आएगी। धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

धनु- कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, योजनाओं को गुप्त रखें। व्यापारिक खर्च बढ़ सकते हैं, संतुलन बनाए रखें। पारिवारिक मामलों में संयम और शांति रखें। अनावश्यक वित्तीय जोखिम लेने से बचें। आंखों में जलन या तनाव हो सकता है। कोर्ट व कचहरी के काम निबटेंगे।

मकर- नौकरी में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। व्यापार में अपेक्षित लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों के साथ सुखद मुलाकात हो सकती है। आय के नए साधन मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी। मेहनत का फल मिलेगा।

कुंभ- प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार में सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन संचय होगा। सेहत अच्छी रहेगी, चुस्ती महसूस होगी।

मीन-धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा, मुनाफा बढ़ेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है। वित्तीय लाभ होगा, स्थिति बेहतर होगी। मानसिक शांति मिलेगी, सेहत उत्तम रहेगी।

10 लाख नौकरियां और 100 अरब डॉलर का निवेश

स्विट्ज़रलैंड के साथ भारत की बड़ी डील

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन की बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्ते नए दौर में प्रवेश कर गए हैं। अब सहयोग सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। दोनों देश निवेश, निर्यात, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में मिलकर काम बढ़ाएंगे। स्विट्जरलैंड में भारतीय सामान की बिक्री बढ़ाने और वहां से ज्यादा निवेश भारत लाने पर सहमति बनी है। दरअसल, पीएम मोदी और स्विस राष्ट्रपति गाइ पार्मेलिन के बीच वार्ता के बाद, भारत और स्विट्जरलैंड ने सोमवार को आव्रजन और आवाजाही साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। साथ ही, उन्होंने भारतीय निर्यात के लिए स्विस बाजार तक पहुंच बढ़ाने और परमाणु ऊर्जा व रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति जताई।



■ बता दें कि पार्मेलिन सोमवार सुबह तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे, जो उनकी इस देश की पहली आधिकारिक यात्रा है। हालांकि, इस वर्ष वह दूसरी बार भारत आए हैं। वह इससे पहले फरवरी में आयोजित 'एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन' में हिस्सा लेने पहुंचे थे। अपने मीडिया बयान में मोदी ने कहा कि स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने और दोनों देशों के बीच निवेश को और आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

■ स्विट्जरलैंड यूरोप में भारत का एक प्रमुख आर्थिक साझेदार है। वर्तमान में इंजीनियरिंग, सेवा, रसायन और दवा जैसे क्षेत्रों में 330 से अधिक स्विस कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि स्विट्जरलैंड में सूचना प्रौद्योगिकी, दवा और मशीनरी जैसे सेक्टरों में भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के देशों-आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड-के बीच 'व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता' (टीईपीए) के अक्टूबर में लागू होने से दोनों पक्षों के बीच व्यापार और निवेश के रिश्तों को और बढ़ावा मिला है।

■ मोदी ने कहा कि टीईपीए निवेश, नवाचार, रोजगार और साझा समृद्धि के लिए एक 'महत्वाकांक्षी खाका' है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से, हम अगले 15 वर्षों में भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अपने लक्ष्यों को साकार करेंगे। प्रधानमंत्री ने नवाचार, बुनियादी ढांचे और उन्नत प्रौद्योगिकी को भारत-स्विट्जरलैंड साझेदारी के मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि दोनों पक्ष सहभागिता को 'नई गति' देने जा रहे हैं।

■ उन्होंने कहा कि हमने स्विट्जरलैंड में भारतीय निर्यात के लिए बाजार तक पहुंच का विस्तार करने और दोनों देशों के बीच निवेश को और सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे स्विट्जरलैंड को भारत के कृषि, दवा, वस्त्र और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि होगी। साथ ही, हम जैवप्रौद्योगिकी, जीव विज्ञान, बैंकिंग, बीमा, खाद्य प्रसंस्करण और स्थिरता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नए स्विस निवेश को आकर्षित करेंगे। इन पहलों के माध्यम से, हम पूरी दुनिया के लिए विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और भरोसेमंद समाधानों का संयुक्त रूप से विकास करेंगे।

■ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों ने परमाणु ऊर्जा में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताने के अलावा सैन्य आदान-प्रदान और रक्षा उत्पादन में सहयोग के लिए 'नई संभावनाओं' की पहचान की। उन्होंने कहा कि वाराणसी में रोपवे, नोएडा में जेवर हवाईअड्डा, और पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे तथा सुरंग निर्माण परियोजनाएं हमारे बुनियादी ढांचे के सहयोग के शानदार उदाहरण हैं। पीएम ने आगे बताया कि परिवहन और बुनियादी ढांचे पर सहयोग के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधारों से कारोबार की सुगमता में होगी वृद्धि, बढ़ेगा भरोसा : पीएम मोदी

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधारों के अगले चरण का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रस्तावित बदलाव कर व्यवस्था को अधिक सरल बनायेंगे तथा कर दायित्वों को लेकर पूर्वानुमान लगाने में आसानी होगी। जीएसटी परिषद की बैठक 7 अक्टूबर को होने जा रही है जिसमें इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधारों के अगले दौर पर चर्चा होने की उम्मीद है।



■ वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने अपने पोस्ट में कहा कि जीएसटी सुधारों का अगला चरण पहले किए जा चुके बदलावों को आगे बढ़ाएगा और कर प्रणाली को करदाताओं के लिए अधिक अनुकूल बनाने पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी के दोहरे उद्देश्यों-करदाताओं को राहत और अर्थव्यवस्था को अधिक गति-को पूरा किया जा रहा है। अगले चरण में पंजीकरण, रिटर्न दाखिल करने, रिफंड, विवाद समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से जुड़े अनुपालन को सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का फोकस अब केवल जीएसटी दरों को अधिक तर्कसंगत बनाने से आगे बढ़कर कर प्रशासन से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार करने पर है। इसका उद्देश्य कारोबारियों और करदाताओं के लिए अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना तथा कर व्यवस्था को अधिक भरोसेमंद बनाना है। सरकार ने पिछले वर्ष जीएसटी प्रणाली में बढ़े बदलाव किये थे। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के फैसलों के तहत 22 सितंबर 2025 को जीएसटी ढांचे में बड़े बदलाव लागू किए गए और अधिकांश उत्पादों को पांच प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत कर के अंतर्गत ला दिया गया। इसके साथ ही 28 प्रतिशत का क्षतिपूरक उपकर भी समाप्त कर दिया गया। जीएसटी की शुरुआत 1 जुलाई 2017 को हुई थी। इसके तहत केंद्र और राज्यों के कई अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत व्यवस्था में लाया गया और देश में एक साझा राष्ट्रीय बाजार तैयार किया गया। इसके बाद से जीएसटी दरों, प्रक्रियाओं और तकनीकी व्यवस्था में कई बदलाव किए जा चुके हैं।

■ वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण की 'एक्स' की एक टिप्पणी को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगली पीढ़ी की जीएसटी प्रणाली कराधान को अधिक सरल बनायेगी तथा उसके बारे में अनुमान लगाना और आसान होगा। इससे अनुपालन आसान होगा, रिफंड प्रक्रिया में सुधार आएगा और कारोबारियों को निवेश तथा विस्तार के लिए अधिक भरोसा मिलेगा। सरकार इन सुधारों को 'विकसित भारत' के लक्ष्य से जोड़कर देख रही है। उन्होंने कहा कि सुधारों से कारोबारी इकाइयों और परिवारों को मदद मिल रही है। मोदी ने कहा कि ये सुधार आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, राजस्व को मजबूत करने और देशभर के उद्यमों के लिए नए अवसर पैदा करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों के अगले चरण में अनुपालन को आसान बनाने और रिफंड प्रक्रिया को बेहतर करने पर ध्यान दिया जाएगा, जिससे कारोबारियों को निवेश और विकास के लिए अधिक विश्वास मिलेगा। इससे विकसित भारत की नींव और मजबूत होगी। पंजीकरण से लेकर रिफंड तक इसका अनुपालन आसान होगा।

■ सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जीएसटी के तहत पंजीकृत करदाताओं की संख्या 2017 में करीब 66.5 लाख थी, जो मई 2026 तक बढ़कर 1.65 करोड़ हो गई। जीएसटी में सुधारों पर विचार के लिए जीएसटी परिषद की कानून संबंधी समिति ने जीएसटी कानूनों के अंतर्गत अपराधिक श्रेणी में रखे गये कृत्यों को गैर-आपराधिक बनाने और प्रवर्तन से जुड़े प्रावधानों में बदलाव के प्रस्तावों पर विचार किया है। परिषद की इस समाप्त होने वाली बैठक में उस पर चर्चा हो सकती है। इसमें केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम की धारा 69 के तहत उपलब्ध गिरफ्तारी की स्वतंत्र शक्ति को हटाने की संभावना भी शामिल है। वर्तमान में धारा 69 के तहत आयुक्त को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति देने का अधिकार है, जिसके बारे में यह मानने के पर्याप्त कारण हों कि उसने सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत निर्धारित अपराध किया है। फर्जी इनवॉइस, फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल करने या उसका गलत इस्तेमाल करने जैसे गंभीर मामलों में इस प्रावधान का इस्तेमाल किया गया है।

सीईसी, एसआईआर और बैलेट पेपर : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने याद दिलाईं तीन शर्तें

सरकार से कहा- इससे कम पर समझौता नहीं

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को चुनावी ढांचे को लेकर पार्टी की ओर से तीन मुख्य मांगें रखी। उन्होंने कहा कि यह मांग ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता है।

- मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा।
- स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (एसआईआर) को रद्द करना।
- बैलेट पेपर से चुनाव कराना।



कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और 'इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ मिलकर इन मांगों के समर्थन में देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

खरगे ने क्या कहा?

खरगे ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी की तीन मांगें ऐसी हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पहली, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, दूसरी, एसआईआर को रद्द करना, तीसरी, बैलेट पेपर से चुनाव कराना। इन तीन मुद्दों को लेकर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता और 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगी सड़कों पर हैं। देश भर में अलग-अलग जगहों पर जो भी नागरिक समाज के सदस्य और युवा संगठन इन मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं।

महिला पत्रकारों के साथ हुई घटना पर क्या कहा?

खरगे ने राजधानी में महिला पत्रकारों के साथ हुई कथित घटना पर भी चिंता जताई और कहा कि दूसरी ओर, भाजपा ने दिल्ली में महिला पत्रकारों को परेशान किया है, जो बहुत निंदनीय है। तानाशाह बहुत घबराया हुआ है। ध्यान भटकाने वाली चालों के एक और अध्याय के लिए तैयार हो जाइए। कांग्रेस अध्यक्ष की ये बातें 3 अक्तूबर को राजधानी में 'ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन' (आइसा) और अन्य समूहों द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ एसआईआर प्रक्रिया को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में आई हैं। जंतर-मंतर के पास हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान, आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल व प्रशांत भूषण समेत कई प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) नेहा यादव के अनुसार, प्रदर्शनकारियों को जगह खाली करने की चेतावनी दी गई थी क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू थी, और बात न मानने पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद, खुद को पत्रकार बताने वाली तीन महिलाओं ने शिकायत दर्ज कराई कि प्रदर्शन स्थल पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी और यौन उत्पीड़न किया।

'झोला उठाने का समय आ गया', दवा की कीमतों को लेकर केंद्र पर बरसी कांग्रेस

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

गंभीर बीमारियों की दवाई की कीमतों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर बड़ा अटैक किया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण देशभर में मरीजों पर महंगी दवाओं का बोझ बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोला उठाकर जाने का समय जल्दी आ रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह सवाल भी किया कि जब कानून मरीजों को राहत देने का रास्ता देता है, तो उस पर आगे बढ़ने में देरी क्यों हो रही है और मरीजों के लिए सस्ती दवा कब सुनिश्चित की जाएगी?



दवाओं के नाम पर वसूली- कांग्रेस

उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण देशभर में मरीजों पर महंगी दवाओं का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नीरो की तरह अपनी अलग ही डफली बजाने में व्यस्त हैं। पार्टी महासचिव ने दावा किया कि देश में मरीजों से दवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर भारी कीमत वसूली जा रही है।

कैंसर के इलाज में साल में लगते हैं 10 लाख

उन्होंने कहा कि 74 रुपए का एक इंजेक्शन 4,980 रुपए में मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों से 67 गुना ज्यादा वसूली की जा रही है। रमेश ने कहा कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की एक दवा की 21 दिन की खुराक की कीमत करीब 58,000 रुपए है, जिससे सालाना खर्च करीब 10 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। रमेश ने कहा कि सवाल सिर्फ एक दवा की कीमत का नहीं, बल्कि पिछले 12 साल से सत्ता में बैठी सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं का है। कांग्रेस महासचिव का कहना है कि पेटेंट कानून की धाराओं 92 और 100 में सार्वजनिक हित तथा सरकारी उपयोग के लिए प्रावधान मौजूद हैं। रमेश ने केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पेटेंट अधिनियम की धारा 100 के तहत सरकार पेटेंट वाली जीवनरक्षक दवा का उत्पादन कर सकती है या उसके अधिकृत उत्पादन की व्यवस्था करके उसे जरूरतमंद मरीजों को गैर-वाणिज्यिक आधार पर उपलब्ध करा सकती है। उन्होंने पूछा कि जब कानून में प्रावधान मौजूद है और उच्च न्यायालय ने भी इसका रास्ता स्पष्ट किया है, तो जीवनरक्षक दवाएं अब भी मरीजों की पहुंच से बाहर क्यों हैं। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मरीजों के लिए सस्ती दवा कब सुनिश्चित होगी? नहीं तो जैसा आपने स्वयं कहा था कि झोला उठाने का समय जल्दी आ रहा है।

पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर भाजपा का मेगा शो

आईजीआई स्टेडियम में होगा भव्य कार्यक्रम

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी बड़े स्तर पर जश्न की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा इस ऐतिहासिक मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि यह कार्यक्रम भाजपा के 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत चल रहे देशव्यापी जश्न का सबसे अहम हिस्सा होगा। इस कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेता, सांसद, विधायक, हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और वहां मौजूद कार्यकताओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तब से लेकर अब तक उनके सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे हो रहे हैं। भाजपा इसे केवल एक राजनीतिक जश्न नहीं बल्कि सेवा और सुशासन के 25 साल के तौर पर मना रही है।



■ इसी कड़ी में 7 अक्टूबर को हरियाणा में 'सेवा ज्योति यात्रा' के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र में सेवा ज्योति यात्रा में शामिल होंगे। वहीं, भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी जींद में सेवा ज्योति यात्रा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। हरियाणा का प्रभारी बनाए जाने के बाद यह उनका राज्य का पहला दौरा होगा, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। पार्टी ने देशभर में सेवा पखवाड़ा, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, युवाओं के साथ संवाद जैसे कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। भाजपा का लक्ष्य इस मौके पर मोदी सरकार की 25 साल की यात्रा और उनके सेवा भाव को जन-जन तक पहुंचाना है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में होने वाला कार्यक्रम इस अभियान का मुख्य आकर्षण होगा, जहां से प्रधानमंत्री मोदी देशभर के कार्यकर्ताओं को सेवा संकल्प का मंत्र देंगे।

अमित शाह जी आप और आपकी पुलिस महिलाओं से डरती क्यों है: राहुल गांधी

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली



कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महिला प्रदर्शनकारियों और पत्रकारों के साथ कथित बदसलूकी को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 'पैटर्न' बन गया है कि जो महिला सवाल पूछे, उसे चुप करा दो। गांधी ने दो महिला पत्रकारों नफीसा खान और शाहीन खान के साथ बातचीत का वीडियो 'एक्स' पर साझा किया और सवाल किया कि गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस महिलाओं से क्यों डरती है? पत्रकार शाहीन और नफीसा ने सितंबर में आरोप लगाया था कि उन्हें एक कार्यक्रम की कवरेज के दौरान हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया, जहां उनके साथ मारपीट की गई। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें 'तथ्यात्मक रूप से गलत' और 'भ्रामक' बताया था।

■ राहुल गांधी ने इन पत्रकारों का उल्लेख करते हुए कहा कि दिल्ली में इस वक्त जो हो रहा है, उसका एक ही पैटर्न है, जो औरत सवाल पूछे, उसे चुप कराओ। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर सैकड़ों लोग हिरासत में लिए गए। महिला प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। महिला पत्रकारों के कैमरे छीने गए, उन्हें घसीटा गया। एक पत्रकार की शिकायत तक दर्ज नहीं हुई। गांधी ने कहा कि कुछ हफ्तों पहले शाहीन और नफीसा ने साकेत थाने के अंदर अपने साथ हुई हिंसा और बदसलूकी की आपबीती सुनाई है। सोचिए, थाने के अंदर वो जगह जहां महिलाएं शिकायत लेकर जाती हैं।

■ उन्होंने आरोप लगाया कि जिन पर महिलाओं की रक्षा की ज़िम्मेदारी है, वही आज उनके लिए खतरा बन रहे हैं। और दिल्ली पुलिस किसके अधीन है, यह पूरा देश जानता है। गांधी ने मांग की कि साकेत थाने का पूरा सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि शाहीन, नफीसा और जिनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने हिंसा और बदतमीजी की है, उनको न्याय मिले। कांग्रेस नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सवाल किया, अमित शाह जी, आप और आपकी पुलिस महिलाओं से डरती क्यों है?

ओमान बना भारत का सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर

सितंबर में अमेरिका को छोड़ा पीछे



हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

भारत के तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) आयात परिदृश्य में सितंबर के दौरान बड़ा बदलाव देखने को मिला। ऊर्जा बाजार के आंकड़ों के अनुसार, ओमान भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा और उसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब भारत पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनावों के बीच अपने ऊर्जा आयात स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति पर लगातार काम कर रहा है। ऊर्जा विश्लेषण कंपनी क्प्लर के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में भारत ने ओमान से 5.85 लाख टन एलएनजी का आयात किया, जो अगस्त की तुलना में 11.6 प्रतिशत अधिक था। इसके साथ ही भारत के कुल एलएनजी आयात में ओमान की हिस्सेदारी लगभग 27 प्रतिशत रही। नाइजीरिया सितंबर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर रहा। हालांकि वहां से आयातित मात्रा 3.51 लाख टन रही, जो पिछले महीने की तुलना में 35 प्रतिशत कम थी। वहीं, अगस्त में भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता रहा अमेरिका तीसरे स्थान पर खिसक गया। अमेरिका से आयात 59 प्रतिशत घटकर सितंबर में लगभग 16 प्रतिशत हिस्सेदारी तक सीमित रह गया। एक समय भारत के एलएनजी आयात का सबसे बड़ा स्रोत रहा कतर भी इस सूची में काफी पीछे चला गया। सितंबर में कतर से केवल 94,000 टन एलएनजी आयात किया गया और वह छठे स्थान पर रहा। इसके मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने 3.11 लाख टन और अंगोला ने 2.05 लाख टन एलएनजी भारत को निर्यात की। विश्लेषकों के अनुसार, कतर की आपूर्ति में आई गिरावट का प्रमुख कारण मार्च में रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हुए हमले का प्रभाव है।

आरटीयू के कुलपति प्रो. डॉ. मानबेंद्र दत्ता चौधरी पर गंभीर आरोप, इस्तीफे और जांच की मांग

पंकज नाथ @ असम

असम के सामाजिक संगठनों में से एक कुटुंब सुरक्षा परिषद ने रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय, होजाई के कुलपति डॉ. मानबेंद्र दत्ता चौधरी पर शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रशासनिक कार्यप्रणाली और वित्तीय मामलों से जुड़ी कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष सत्य रंजन बोरा ने राज्यपाल से मामले में तत्काल उचित कार्रवाई करने और कुलपति से स्वेच्छा से इस्तीफा देने की मांग की। गुवाहाटी प्रेस क्लब में शुक्रवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोरा ने कहा कि परिषद विश्वविद्यालय जैसे सार्वजनिक संस्थान के प्रति नागरिकों की संवैधानिक जिम्मेदारी को गंभीरता से लेती है। उन्होंने दावा किया कि परिषद की ओर से राज्यपाल, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को इस संबंध में लिखित आवेदन भेजे गए हैं। बोरा के अनुसार, 14 मई 2024 को राज्यपाल सचिवालय की ओर से विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए ऐसे प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था, जिन्हें प्रोफेसर के रूप में कम-से-कम 10 वर्ष का अनुभव हो। उन्होंने आरोप लगाया कि आवेदन-पत्र में वित्तीय अनियमितताओं और आपराधिक मामलों से संबंधित जानकारी मांगी गई थी, लेकिन डॉ. चौधरी की नियुक्ति के संदर्भ में इन बिंदुओं की पर्याप्त जांच नहीं हुई। परिषद ने आरोप लगाया कि असम विश्वविद्यालय, सिलचर में डॉ. चौधरी को 2011 में प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया, जबकि यूजीसी मानदंडों के अनुसार उनकी पात्रता 2017 में पूरी होती थी। बोरा ने इस दावे के समर्थन में असम विश्वविद्यालय के पंजीयक द्वारा 2020 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में दायर एक हलफनामे का हवाला दिया और मामले का नंबर WP(C) 3359/2019 बताया। उन्होंने यह भी कहा कि डॉ. चौधरी के दो कथित नौकरी आवेदन-पत्रों में पीएचडी पूरी करने का वर्ष अलग-अलग दर्ज है-एक में 2000 और दूसरे में 1999। परिषद ने इन दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिषद ने आरोप लगाया कि कुलपति प्रत्येक माह लगभग 10 से 15 दिन विश्वविद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं और उनकी अनुपस्थिति से नियमित प्रशासनिक कार्य प्रभावित होते हैं। बिना निविदा प्रक्रिया के कुछ कार्य कराने तथा नए परिसर की कैंटीन



आवंटित करने का आरोप भी लगाया गया। बोरा ने यह भी आरोप लगाया कि कुलपति ने अपने परिवार अथवा परिचितों से जुड़े कुछ लोगों को बाहर से लाकर हिंदी, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान सहित विभिन्न विभागों में नियुक्त कराया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है। शुल्क और वित्तीय अनियमितता का आरोपपरिषद ने विश्वविद्यालय में नियुक्तियों, छात्र प्रवेश और शुल्क निर्धारण में कथित वित्तीय अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया। बोरा के अनुसार, पीएचडी प्रवेश के लिए 76,000 रुपए तक शुल्क लिया जा रहा है, जबकि असम के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में यह शुल्क 15,000 से 26,000 रुपए के बीच है। उन्होंने बाद में शुल्क 58,000 रुपए किए जाने और विश्वविद्यालय के कार्यवाहक पंजीयक की पत्नी के पीएचडी में प्रवेश को लेकर भी सवाल उठाए। परिषद ने डॉ. चौधरी की पत्नी प्रो. करबी दत्ता चौधरी की करिमगंज कॉलेज में नियुक्ति तथा त्रिपुरा के एक महिला विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए उनके कथित शॉर्टलिस्ट किए जाने पर भी आपत्ति जताई। बोरा ने डॉ. चौधरी के खिलाफ 2011 में सिलचर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 379, 506 और 34 के तहत दर्ज कथित मामले का भी उल्लेख किया और सवाल उठाया कि कुलपति पद के आवेदन के समय यह जानकारी घोषित की गई थी या नहीं। कुटुंब सुरक्षा परिषद ने राज्यपाल और संबंधित सरकारी अधिकारियों से सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने, नियुक्ति तथा वित्तीय अभिलेखों की समीक्षा करने और जांच पूरी होने तक आवश्यक प्रशासनिक कदम उठाने की मांग की है।

अमेरिका से आए जैक्सन ने काशी में किया चाचा का पिंडदान!

विधि-विधान से किया पिंडदान



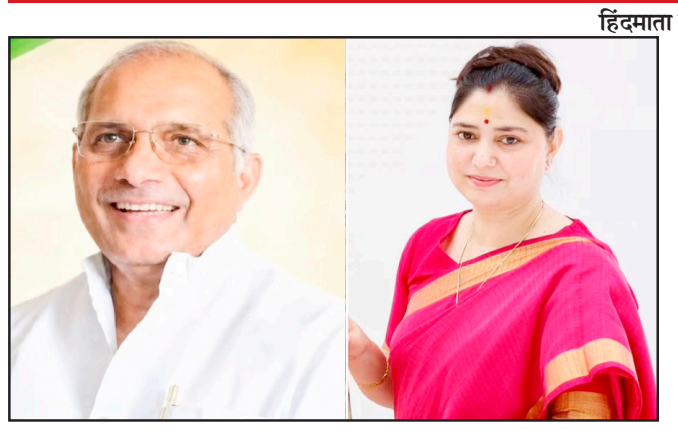
हिंदमाता नेटवर्क @ वाराणसी

काशी की आध्यात्मिक आस्था और सनातन परंपराओं का आकर्षण सात समंदर पार रहने वाले लोगों को भी यहां खींच लाता है। पितृ पक्ष में अमेरिका के मिशिगन से जैक्सन अपने दिवंगत चाचा नेट की अस्थियां लेकर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने गंगा तट पर हिंदू विधि-विधान के अनुसार अस्थि विसर्जन के साथ तीर्थ श्राद्ध और पिंडदान की धार्मिक प्रक्रिया पूरी की। अस्थि विसर्जन और श्राद्ध कर्म का पूजन पुरोहित राहुल पांडेय ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच कराया। राहुल पांडेय ने बताया कि जैक्सन ने गंगा में अपने चाचा की अस्थियां प्रवाहित करते हुए उनकी आत्मा की शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद विधि-विधान से तर्पण और पिंडदान की प्रक्रिया भी संपन्न हुई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है। वहीं काशी में पूर्वजों के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। इसी आस्था के चलते देश ही नहीं, विदेशों से भी लोग अपने दिवंगत परिजनों के अंतिम संस्कार और धार्मिक कर्मकांड के लिए काशी पहुंचते हैं। पिंडदान के दौरान दिवंगत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और स्मरण प्रकट किया जाता है, जबकि तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। सनातन परंपरा में इसे दिवंगत परिजनों के प्रति परिजनों का धार्मिक दायित्व भी माना जाता है। मिशिगन से हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर काशी पहुंचे जैक्सन ने अपने चाचा की अस्थियों का गंगा में विसर्जन कर अंतिम धार्मिक दायित्व पूरा किया। गंगा तट पर पूरे श्रद्धाभाव से हुए इस अनुष्ठान में काशी की आध्यात्मिक परंपरा और सनातन संस्कृति की वैश्विक पहुंच की झलक देखने को मिली। पुरोहित राहुल पांडेय ने बताया कि काशी में अस्थि विसर्जन, तीर्थ श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा सदियों पुरानी है। देश-विदेश से श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए काशी आते हैं।

राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवार घोषित

धर्मपाल सिंह-प्रियंका रावत समेत 8 नए नाम

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ



उत्तर प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रत्याशियों को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी की ओर से जारी सूची में 3 ओबीसी, 2 एससी और 3 सामान्य वर्ग के उम्मीदवार शामिल हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। वहीं, उम्मीदवारों में 2 ब्राह्मण और 1 राजपूत शामिल हैं। ओबीसी वर्ग में 1 लोधी, 1 पाल और 1 कुर्मी उम्मीदवार हैं।

धर्मपाल सिंह लोधी बिरादरी से आते हैं। वह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। प्रकाश पाल संगठन में क्षेत्रीय मंत्री हैं और पाल बिरादरी से आते हैं। ओबीसी समुदाय में पाल को गडेरिया बिरादरी माना जाता है। विद्यासागर सोनकर दलित बिरादरी से हैं और पार्टी के अहम पदों पर रह चुके हैं। वह पूर्व एमएलसी और मछलीशहर से पूर्व सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा वह पार्टी के पूर्व महामंत्री भी हैं। इस लिस्ट में मंत्री हरदीप पुरी और बीएल वर्मा का नाम नहीं आया है।

इस बार नए चेहरों को मिला मौका

इस बार बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए सभी नए चेहरों को मौका दिया है। पुराने चेहरों को इस बार उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इनमें अरुण सिंह, सीमा द्विवेदी, बीएल वर्मा, हरदीप सिंह पुरी, नीरज शेखर, बृजलाल, दिनेश शर्मा और गीता शाक्य शामिल हैं। दिनेश शर्मा अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल हैं।

■ धर्मपाल सिंह

धर्मपाल सिंह बरेली के आंवला से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। वह कई बार विधायक रह चुके हैं और फिलहाल यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनके पास पशुपालन और डेयरी विकास विभाग की जिम्मेदारी है।

■ विद्यासागर सोनकर

विद्यासागर सोनकर जौनपुर और पूर्वी यूपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। वह 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए सैदपुर (एससी) से सांसद चुने गए थे।

■ प्रियंका सिंह रावत

प्रियंका सिंह रावत बीजेपी की पूर्व लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने 2014 का लोकसभा चुनाव बाराबंकी से जीता था। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया को हराया था।

■ राम प्रताप सिंह चौहान

राम प्रताप सिंह चौहान यूपी बीजेपी के वरिष्ठ संगठन नेता हैं। जून 2026 में यूपी बीजेपी में हुए बदलाव के दौरान उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाया गया था। अगस्त 2026 में उन्हें पश्चिमी यूपी के संगठनात्मक क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई।

■ प्रकाश पाल

प्रकाश पाल बीजेपी के वरिष्ठ संगठन नेता और यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वह पहले बीजेपी के कानपुर-बुंदेलखंड संगठनात्मक क्षेत्र की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं।

शॉर्ट स्टोरी

बिहार एमएलसी चुनाव में आरजेडी-कांग्रेस आमने-सामने

हिंदमाता नेटवर्क @ पटना



बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन के घटक दलों राजद, कांग्रेस और लेफ्ट में सीट बंटवारे का विवाद गहरा गया है। गठबंधन के प्रमुख दल कुल 8 सीटों में से 6 सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर आमने-सामने आ गए हैं।चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर हो रही है। इस सीट पर कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी मदन मोहन झा चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ सहयोगी पार्टी राजद ने कुंवर राय को अपना उम्मीदवार बना दिया है। इतना ही नहीं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने भी अपने प्रत्याशी रामदेव राय को यहां से मैदान में उतारा है। इस तरह दरभंगा शिक्षक सीट पर एक ही गठबंधन के तीन दल आपस में टकरा रहे हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में भी राजद और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पटना स्नातक सीट पर राजद के दिलीप कुमार का सामना कांग्रेस के डॉ. असदुल्लाह खान से होगा। दरभंगा स्नातक सीट पर राजद के अनिल कुमार झा और कांग्रेस के रजनीकांत पाठक आमने-सामने खड़े हैं। इसी तरह कोसी स्नातक सीट पर राजद उम्मीदवार नितेश कुमार और कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार जायसवाल के बीच सीधा टकराव तय हो चुका है। शिक्षक सीटों पर भी सहयोगियों की जंग जारी है। पटना शिक्षक सीट पर राजद के डॉ. संजीव कुमार सिंह और कांग्रेस के संजय यादव एक-दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। वहीं, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में राजद के प्रो. जयराम यादव का सीधा मुकाबला सीपीआई के उम्मीदवार विद्यासागर विद्यार्थी से हो रहा है।

कांग्रेस का बार्गेनिंग दांव या सपा से अलग राह पकड़ने का बैकअप प्लान?

यूपी में नया चक्रव्यूह

हिंदमाता नेटवर्क @ लखनऊ

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। सपा और कांग्रेस भले ही एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हों, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर राजनीतिक खींचतान जारी है। अखिलेश यादव जीत की शर्त रखकर सीट शेयरिंग करना चाहते हैं, वहीं कांग्रेस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए व्यूह रचने में जुट गई है। सपा से दूरी बना चुके और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) राजनीति का बड़ा चेहरा माने जाने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) के संजय चौहान और अपना दल (कामेरवादी) के पंकज निरंजन जैसे नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। इन मुलाकातों ने सूबे के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इसे मुख्य रूप से तीन बड़े सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। यूपी में छोटे दलों के नेताओं को अपने साथ मिलाकर कांग्रेस अपना सियासी ताना-बाना बुन रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहती है या यह सपा से अलग होने का बैकअप प्लान है?

बार्गेनिंग पावर बढ़ाने में जुटी कांग्रेस

उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद लगातार सीट शेयरिंग का मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस सूबे में बड़ी हिस्सेदारी पर मजबूती से दावा पेश करने की तैयारी में है। अखिलेश यादव जहां कांग्रेस को सिर्फ सीमित और 'जीतने योग्य' सीटें ही देने के पक्ष में हैं, वहीं कांग्रेस छोटे क्षेत्रीय दलों और जातिगत जनाधार वाले नेताओं को जोड़कर यह संदेश देना चाहती है कि उसका आधार केवल कागजी नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य, संजय चौहान और पंकज निरंजन तीनों ही गैर-यादव ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। सपा ने इन नेताओं को 2022 के चुनाव में अपने साथ लेकर भाजपा को कड़ी टक्कर दी थी, क्योंकि इन नेताओं का अपना जनाधार है। कांग्रेस ने इन्हें अपने पाले में लाकर नया दांव चला है। छोटे दलों को अपने साथ जोड़ने या अपने सिंबल पर चुनाव लड़ाने का खाका दिखाकर कांग्रेस सीट शेयरिंग की बातचीत में सपा के सामने ज्यादा मजबूत स्थिति में मोलभाव करने की योजना बना रही है।



क्या यह कांग्रेस का बैकअप प्लान है?

उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2024 की तरह आगामी विधानसभा चुनाव में केवल सीमित सीटों पर समझौता नहीं करना चाहती, बल्कि सपा के साथ बराबर का सियासी कद चाहती है। पार्टी करीब 150 सीटों को चिह्नित कर अपनी तैयारी कर रही है और 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य रख रही है। इसी रणनीति के तहत छोटे दलों के नेताओं को साथ लाने का दांव खेला गया है।

छोटे दलों का कांग्रेस से हाथ मिलाना

2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले कई छोटे दल बाद में अलग हो गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य और संजय चौहान ने सपा से नाता तोड़कर अपनी अलग राजनीतिक राह चुन ली थी। अखिलेश यादव ने भी इस बार इन छोटे दलों से अलग से सौदेबाजी करने से दूरी बना रखी है। यूपी में इन छोटे दलों को अपना अस्तित्व बचाने और चुनाव में अपनी शर्तें मनवाने के लिए कांग्रेस ही एकमात्र राष्ट्रीय विकल्प दिख रही है।

दारोगा भर्ती एग्जाम को लेकर पटना में प्रदर्शन

हिंदमाता नेटवर्क @ पटना



इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। यहां दारोगा भर्ती परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद अभ्यर्थियों का प्रदर्शन तेज हो गया है। परीक्षा रद्द करने के विरोध में अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र परीक्षा रद्द किए जाने के बाद से आक्रोशित हैं। यहां बता दें कि दारोगा भर्ती की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के खुलासे के बाद एग्जाम को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद एग्जाम में पास अभ्यर्थियों में आक्रोश है। वहीं दारोगा भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और वे आगे डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ गए हैं। पटना में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। पुलिस लगातार अभ्यर्थियों को रोकने का प्रयास कर रही है, इसके बावजूद आक्रोशित अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने पटना में पुलिस की लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। वहीं अब अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे की तरफ बढ़ रहे हैं। बता दें कि इससे पहले दारोगा भर्ती को लेकर हुई लिखित परीक्षा को गड़बड़ी के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था। यह परीक्षा 27 मई को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के बाद से ही लगातार धांधली के आरोप लगाए जा रहे थे। वहीं कई अभ्यर्थी परीक्षा की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे थे। ऐसे में छात्रों की मांग को मानते हुए परीक्षा को रद्द कर दिया गया। हालांकि अब वे अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनका मानना है कि यह परीक्षा रद्द नहीं की जानी चाहिए थी। गौरतलब है कि दारोगा भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने खूब प्रदर्शन किया था। पटना में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। दरअसल बिहार दारोगा भर्ती परीक्षा 27 मई को हुई थी और इस परीक्षा के जरिए कुल 1799 पद भरे जाने थे।

कानपुर में सरकारी डॉक्टर ने किया सुसाइड, पत्नी से विवाद के बाद खुद को मारी गोली

हिंदमाता नेटवर्क @ कानपुर

कानपुर के साकेत नगर क्षेत्र में एक सरकारी डॉक्टर ने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरूआती जांच में डॉक्टर के पत्नी से विवाद के बाद आत्मघाती कदम उठाने की बात सामने आ रही है। मृतक की पहचान डॉ. संदीप सिंह के रूप में हुई है। वह सरकारी डॉक्टर थे। बताया जा रहा है कि डॉ. संदीप सिंह अपनी पत्नी के साथ परिवार से अलग साकेत नगर स्थित एक किराए के फ्लैट में रहते थे। मृतक की तैनाती कानपुर देहात में बताई जा रही है।

पत्नी से विवाद के बाद मारी गोली

पुलिस के मुताबिक, पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। सोमवार को भी दोनों के बीच विवाद होने की बात सामने आई है। इसके बाद डॉ. संदीप सिंह ने अपनी रिवाल्वर से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फ्लैट की जांच की और घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए। रिवाल्वर को भी कब्जे में लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना के कारणों की पुष्टि के लिए परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, हालांकि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।



परिवार में मचा कोहराम

घटना की सूचना मिलते ही डॉक्टर के परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पति-पत्नी के बीच विवाद किस वजह से हुआ था और क्या आत्महत्या से पहले डॉक्टर ने किसी से बातचीत की थी। जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

नहाने समय नदी में डूब गया था युवक, चंद्रमा ऋषि आश्रम के पास मिली बाइक

हिंदमाता नेटवर्क @ आजमगढ़



देवखरी गांव निवासी झारखंडेय उपाध्याय (36) रविवार सुबह बुलेट बाइक से घर से निकला था। दोपहर में वह चंद्रमा ऋषि आश्रम पहुंचा। यहां बुलेट खड़ी करने के बाद उसने कपड़े उतारे और नदी में नहाने चला गया। काफी देर बाद भी जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता हुई। देर शाम तक उसका पता नहीं चलने पर परिवार के लोग उसकी तलाश में जुट गए।

परिजनों में कोहराम

रात करीब 10 बजे परिजनों को जानकारी मिली कि चंद्रमा ऋषि आश्रम के पास झारखंडेय की बुलेट खड़ी है। इसके बाद परिवार के लोग और गांव के अन्य लोग आश्रम पहुंचे। वहां बुलेट के पास युवक के कपड़े भी पड़े मिले। इससे लोगों को उसके नदी में डूबने की आशंका हुई। ग्रामीणों और परिजनों ने देर रात तक आसपास के इलाके और नदी में उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके बाद सभी लोग घर लौट गए। सोमवार सुबह कंधेनपुर गांव के पास नदी में लोगों ने एक युवक का शव पानी में उतराया देखा। इसकी सूचना कंधरापुर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर कब्जे में लिया।

गया जेल में मिला अतीक गैंग का 5 लाख का इनामी शूटर, 2023 से थी तलाश

हिंदमाता नेटवर्क @ प्रयागराज

बिहार के गया सेंट्रल जेल में बंद अतीक गैंग के शूटर मो. अरमान को रविवार शाम यूपी पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज ले गई। प्रयागराज पुलिस टीम उसे ले जाने के लिए गया जी पहुंची थी। जेल प्रशासन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शाम करीब 5 बजे अरमान को गुप्त तरीके से पुलिस टीम अपने साथ लेकर रवाना हो गई। प्रयागराज में चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में अरमान आरोपी है और उस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। करीब साढ़े तीन साल से गया जी जेल में बंद अरमान के बाहर निकलने की भनक लगते ही परिजन जेल गेट पर पहुंच गए, लेकिन तब तक पुलिस उसे लेकर निकल चुकी थी। एसएसपी सुशील कुमार ने अरमान को यूपी पुलिस द्वारा ले जाए जाने की पुष्टि की है।



परिजन जेल गेट पर करते रहे इंतजार

मो. अरमान के छोटे भाई इमरान ने बताया कि सूचना मिलने पर वे लोग भाई से मिलने जेल पहुंचे। जेल प्रशासन से अरमान के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। जेल के बाहर गेट पर इंतजार करते रहे। बाद में पता चला कि शाम 5 बजे ही यूपी पुलिस अरमान को लेकर निकल चुकी है।

प्राइवेट पार्ट काटकर जाते दिखा प्रेमानंद का शिष्य, सामने आया नया सीसीटीवी

हिंदमाता नेटवर्क @ मथुरा

मथुरा के वृंदावन स्थित प्रेमानंद महाराज के गुरु कृपा कुंज आश्रम में रसिक दुलारी शरण उर्फ दीपक लोधी की मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। अब घटना से जुड़ा एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में दीपक लोधी अपना प्राइवेट पार्ट काटने के बाद सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसके तुरंत बाद उसने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी थी। हालांकि, सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद लगाए जा रहे इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पूरे घटनाक्रम की तस्वीर पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो सकेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर दीपक लोधी ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया।

प्राइवेट पार्ट काटने के बाद कहां गया दीपक?

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में दीपक लोधी सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि यह फुटेज उस घटना के बाद का है, जिसमें उसने कथित तौर पर अपना प्राइवेट पार्ट काट लिया था। इसके बाद उसके चौथी मंजिल तक पहुंचने और वहां से नीचे गिरने की बात कही जा रही है। अगर यह घटनाक्रम जांच में सही पाया जाता है तो यह वीडियो उसकी मौत से पहले के आखिरी पलों की अहम कड़ी साबित हो सकता है। फिलहाल नया सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद दीपक लोधी की मौत का रहस्य और गहरा गया है।



मौत के पीछे की वजह अब भी रहस्य

दीपक लोधी ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। परिवार और उसके करीबियों की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उसकी मौत के बाद से ही आश्रम के बाहर लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। लोग मामले की निष्पक्ष जांच और घटना की पूरी सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं। इस बीच राधा केलि कुंज ट्रस्ट की ओर से सोशल मीडिया पर एक अपील जारी की गई है। आश्रम प्रबंधन ने पुष्टि की है कि यह अपील उसी की ओर से जारी की गई है। बयान में कहा गया है कि हाल में हुई घटना से पूज्य महाराज जी और समस्त परिकर अत्यंत आहत हैं।

गाजियाबाद में रावण के पुतले में पटाखे भरते समय धमाका

हिंदमाता नेटवर्क @ गाजियाबाद



गाजियाबाद में दशहरा से पहले रावण के पुतले की तैयारी के दौरान बड़ा हादसा हो गया। साहिबाबाद के लाजपत नगर स्थित नगर निगम के सामुदायिक केंद्र में 5 अक्टूबर की सुबह रावण के पुतले में पटाखे भरते समय अचानक जोरदार धमाका हो गया। धमाके की चपेट में आकर पांच लोग झुलस गए। इनमें कुछ नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। विस्फोट इतना तेज था कि सामुदायिक केंद्र के बड़े हॉल की दो दीवारें भी क्षतिग्रस्त होकर गिर गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घटना 5 अक्टूबर की सुबह करीब 9:26 बजे की है। फायर विभाग के मुताबिक, साहिबाबाद फायर स्टेशन के कंट्रोल रूम को रामलीला मैदान, शनि चौक के पास पटाखों की दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी। जानकारी मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी, साहिबाबाद के प्रभारी अग्निशमन अधिकारी और तीन फायर टेंडर मौके के लिए रवाना किए गए। दमकल की टीम जब घटनास्थल पर पहुंची तो मामला पटाखों की दुकान में आग लगने का नहीं, बल्कि रामलीला मैदान के पीछे बने सामुदायिक केंद्र के एक बड़े हॉल में आग लगने का सामने आया। फायर कर्मियों ने तत्काल कार्यवाही करते हुए आग पर काबू पाया। इसके बाद हॉल का निरीक्षण करने पर पता चला कि वहां रामलीला के लिए रावण का पुतला तैयार किया जा रहा था। इसी दौरान पुतले के अंदर पटाखे और आतिशबाजी की सामग्री भरी जा रही थी, तभी अचानक आग भड़क उठी और धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि रावण का पुतला तैयार करने का ठेका रामलीला कमेटी ने अनिल सिंह नाम के व्यक्ति को दिया था।

हिंदमाता एंकरः 170 से ज्यादा भवनों को जमींदोज किया जा चुका है, पीडब्ल्यूडी के मुताबिक करीब 172 से 173 मकान पूरी तरह डिस्मेंटल किए जा चुके हैं

बुलडोजर ने बदली दालमंडी की तस्वीर, 187 भवन हटे, अब काशी विश्वनाथ का रास्ता होगा 60 फीट चौड़ा

हिंदमाता संवाददाता @ वाराणसी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए दालमंडी से होकर बनाए जा रहे सुगम मार्ग के चौड़ीकरण का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। करीब एक साल पहले शुरू हुए इस प्रोजेक्ट के तहत दालमंडी इलाके में ध्वस्तीकरण का काम लगभग पूरा हो गया है। सोमवार को पांच और भवनों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके साथ ही चौड़ीकरण की जद में आए भवनों को हटाने का काम पूरा होने की बात पीडब्ल्यूडी ने कही है। दालमंडी में चल रहा यह प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते को पहले के मुकाबले काफी चौड़ा करने के लिए शुरू किया गया था। पीडब्ल्यूडी की ओर से करीब सवा 200 करोड़ रुपये की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के तहत दालमंडी इलाके में कुल 187 भवन चौड़ीकरण की जद में आए थे। इन भवनों में छह मस्जिदें भी शामिल थीं। अब तक 170 से ज्यादा भवनों को जमींदोज किया जा चुका है। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक करीब 172 से 173 मकान पूरी तरह डिस्मेंटल किए जा चुके हैं। बचे हुए भवनों पर भी आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया था। सोमवार को अंतिम चरण में पांच भवनों को गिराया गया। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट के तहत भवनों को हटाने का काम पूरा हो गया। दालमंडी का इलाका लंबे समय से संकरी गलियों और घनी आबादी के लिए जाना जाता है। इसी इलाके से होकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने वाले रास्ते को चौड़ा किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत करीब 60 फीट चौड़ी और साढ़े 600 मीटर लंबी सड़क तैयार की जानी है।

गलियों के जाल से निकलेगा 60 फीट चौड़ा रास्ता



इस चौड़ी सड़क के तैयार होने के बाद मंदिर तक पहुंचने का रास्ता मौजूदा संकरी गलियों के मुकाबले काफी सुगम हो जाएगा। फिलहाल इस पूरे इलाके में चौड़ीकरण की जद में आए भवनों को हटाने का काम लगभग पूरा किया जा चुका है। अब आगे का काम सड़क और उससे जुड़ी सुविधाओं को तैयार करने पर केंद्रित होगा। दालमंडी चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के तहत कुल 187 भवनों की पहचान की गई थी। इनमें छह मस्जिदें भी शामिल थीं। प्रशासन ने मस्जिद कमेटी के सहयोग से इन मस्जिदों को भी चौड़ीकरण की जरूरत के अनुसार आंशिक या पूर्ण रूप से हटाया है। भवनों को हटाने का काम चरणबद्ध तरीके से किया गया। अब अंतिम चरण में पांच भवनों को भी डिस्मेंटल कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के मुताबिक इसके साथ ही डिमोलिशन का अंतिम चरण पूरा हो गया है। पीडब्ल्यूडी के वाराणसी के अधिशासी अभियंता केके सिंह ने बताया कि दालमंडी में डिस्मेंटलिंग का फाइनल चरण सोमवार को था। इस चरण में करीब पांच भवनों को डिस्मेंटल किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक 172 से 173 मकान पूरी तरह डिस्मेंटल किए जा चुके हैं।

अब वाटर लाइन और सीवर लाइन का काम

दालमंडी चौड़ीकरण का यह प्रोजेक्ट करीब एक साल तक चलने वाला था। अधिकारियों के मुताबिक इसे दिसंबर में पूरा करना बड़ी उपलब्धि होगी। इसके लिए भवनों के ध्वस्तीकरण के साथ-साथ सड़क से जुड़ी अन्य व्यवस्थाओं पर भी काम किया जा रहा है। केके सिंह ने बताया कि इस काम में प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। इसी सहयोग के चलते ध्वस्तीकरण के काम को अंतिम चरण तक पहुंचाया जा सका है। अब दालमंडी में भवनों को हटाने का काम खत्म हो चुका है और सड़क निर्माण से जुड़े बाकी काम को पूरा करने पर जोर है। करीब एक साल पहले शुरू हुआ यह काम अब उस मुकाम पर पहुंच गया है, जहां दालमंडी में चौड़ीकरण की सबसे बड़ी बाधा यानी भवनों को हटाने का काम पूरा हो चुका है। 60 फीट चौड़ी और साढ़े 600 मीटर लंबी सड़क के तैयार होने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्ते को नया स्वरूप मिलेगा। अधिकारियों की योजना के मुताबिक नवंबर में वाटर लाइन और सीवर लाइन का काम पूरा होगा और इसके बाद करीब एक से डेढ़ महीने में पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर दिसंबर के अंत तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।

रूस में प्लेग का खौफ!

महिला रिसर्चर की मौत के बाद 200 लोग क्वारंटीन में भेजे गए



हिंदमाता नेटवर्क @ मॉस्को

रूस के साइबेरिया में एक एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट की 28 साल की रिसर्चर की गंभीर निमोनिया से मौत के बाद हड़कंप मच गया है। रिसर्चर की मौत के बाद करीब 200 लोगों को मेडिकल निगरानी में रखा गया है और कुछ जगहों पर एहतियाती क्वारंटीन जैसे कदम उठाए गए हैं। हालांकि, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बीमारी प्लेग थी। रूसी स्वास्थ्य अधिकारियों ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इरकुत्स्क एंटी-प्लेग इंस्टीट्यूट में काम करने वाली दर्या शिपिलोवा को 29 सितंबर को गंभीर निमोनिया के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन दो दिन बाद उनकी मौत हो गई। बताया गया है कि वह पड़ोसी बुर्यातिया में फील्ड एक्सपीडिशन पर थीं, जहां उन्होंने तबीयत बिगड़ने से पहले मेडिकल स्टाफ को बताया था कि उनसे गलती से जिंदा बैक्टीरिया वाली एक टेस्ट ट्यूब टूट गई थी।

करीब 200 लोग निगरानी में

रूसी पब्लिक हेल्थ वॉचडॉग रोस्पोट्रेबनादजोर ने बीमारी को अज्ञात कारणों से हुआ निमोनिया बताया है। एजेंसी के मुताबिक, रिसर्चर के शरीर में उनके पेशेवर काम से जुड़े किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म का पता नहीं चला। इसके बावजूद उन लोगों को ट्रेस किया गया, जो रिसर्चर के संपर्क में आए थे। अनौपचारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 200 लोगों को शेलखोव अस्पताल में क्वारंटीन या मेडिकल निगरानी में रखा गया। क्षेत्र के तीन अस्पतालों में भी एहतियाती कदम उठाए जाने की बात सामने आई है।

जुलाई में ही फ्लाईदुबई प्लेन को हाईजैक करने वाला था ओमानी को-पायलट

क्रू दोस्त की वजह से टाला हमला



हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

30 सितंबर को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाईदुबई की फ्लाइट एफजेड1073 के कॉकपिट में भारतीय कैप्टन स्मित मछार पर जानलेवा हमला करने वाले ओमानी को-पायलट हमाम अल-हम्मामी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, हम्मामी ने इस 9/11 स्टाइल आतंकी हमले की साजिश जुलाई में ही रच ली थी, लेकिन एयरलाइन के एक क्रू सदस्य से दोस्ती के चलते उस समय अपना प्लान टाल दिया। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अल-हम्मामी ने 30 सितंबर को होने वाले हमले की योजना फ्लाईदुबई में नौकरी शुरू करने से पहले ही बना ली थी। वह कथित तौर पर 9/11 जैसे हमले को अंजाम देना चाहता था। उसकी योजना दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट एफजेड1073 को तेल अवीव की किसी ऊंची इमारत या बेन गुरियन एयरपोर्ट पर क्रैश कराने की थी। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक, अल-हमामी ने संयुक्त अरब अमीरात के जांचकताओं को बताया कि उसने फ्लाईदुबई में नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले उन एयरलाइनों की तलाश की थी, जो तेल अवीव (इजरायल) के लिए उड़ानें संचालित करती हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि फ्लाईदुबई के साथ काम करने के दौरान उसने बेन गुरियन एयरपोर्ट का कई बार दौरा किया था। जून में एक यात्रा के दौरान उसने एयरपोर्ट से जुड़ी जानकारी जुटाई और कथित तौर पर हमले की योजना को आगे बढ़ाया।

इजरायल की एविएशन सिक्योरिटी पर भी सवाल

इस पूरे मामले ने इजरायल की विमानन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ओमान जैसे उन देशों के नागरिक, जिनके इजरायल के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं, उन्हें इजरायल जाने वाली उड़ानों का संचालन करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद अल-हमामी को तेल अवीव रूट पर कैसे तैनात किया गया, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

पहले भी उठ चुके थे सवाल

इस मामले ने यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि अल-हमामी फ्लाईदुबई में नौकरी हासिल करने और तेल अवीव रूट पर उड़ान संचालित करने में कैसे सफल रहा, जबकि उसके पुराने रिकॉर्ड को लेकर पहले ही चिंताएं सामने आ चुकी थीं। ओमानी अधिकारियों ने अल-हमामी की ऑनलाइन गतिविधियों की जांच की थी और उसके कट्टरपंथी विचारों में अत्यधिक रुचि को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद उसे ओमान एयर में उड़ान भरने से रोक दिया गया था और बाद में डेस्क जॉब दे दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक, ओमान ने इन चिंताओं की जानकारी व्यापक स्तर पर दूसरी एजेंसियों या एयरलाइंस के साथ साझा नहीं की। इसके बाद फरवरी में फ्लाईदुबई ने उसे नौकरी दे दी।

बिजनेस वर्ल्ड

एयर फेयर में बड़ा इजाफा! इंडिगो ने लागू किया नया फ्यूल चार्ज, कितना बढ़ा किराया

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली



हाल ही में पेट्रोलियम कंपनियों ने कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होने के कारण 1 अक्टूबर से जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया था। ये इजाफा 13 फीसदी से ज्यादा था। खास बात तो ये है कि बीते तीन महीने में जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफा होने से ये बढ़ोतरी करीब 25 फीसदी तक हो चुकी है। जिसकी वजह से देश की सबसे बड़ी डॉमेस्टिक एयरलाइन इंडिगो ने अपने फ्यूल सरचार्ज में इजाफा कर दिया है। जिसकी वजह से आने वाले दिनों में इंडिगो से हवाई सफर करना महंगा हो सकता है। ये इजाफा दूरी और जगह के आधार पर है। ये सरचार्ज 6 अक्टूबर यानी मंगलवार से लागू हो जाएंगे। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इंडिगो की ओर से किस तरह का अपडेट सामने आया है। इंडिगो ने सोमवार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर फ्यूल चार्ज बढ़ाने का ऐलान किया है। जिसकी सबसे बड़ी वजह जेट फ्यूल की कीमतों में इजाफा है। ये नए चार्ज 6 अक्टूबर, 2026 को रात 12:01 बजे से की जाने वाली सभी नई बुकिंग पर लागू होंगे। घरेलू उड़ानों के लिए, दूरी के आधार पर फ्यूल चार्ज प्रति सेक्टर 375 रुपए से 1,300 रुपए के बीच होगा। इंटरनेशनल रूट के लिए ये चार्ज 1,000 रुपए से 10,000 रुपए के बीच होगा। जेट फ्यूल के दाम 1 अक्टूबर से 121 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर लगभग 137 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। यह लगातार तीसरी मासिक बढ़ोतरी है। इससे पहले अगस्त में कीमतें 5 रुपए प्रति लीटर और सितंबर में 6.28 रुपए प्रति लीटर बढ़ी थीं। इंडिगो ने कहा कि पिछले महीने की तुलना में फ्यूल की कीमतों में 14 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, जिससे एटीएफ की लागत पिछले एक दशक में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। एयरलाइन के कामकाज की लागत में एटीएफ का बड़ा हिस्सा होता है और यह एयरलाइन की लागत संरचना और नेटवर्क इकोनॉमिक्स पर असर डालता है। इंडिगो ने पिछली बार अप्रैल में अपने घरेलू फ्यूल चार्ज में बदलाव किया था, जब उसने दूरी के आधार पर चार्ज तय करने का सिस्टम अपनाया था, जिसमें हर सेक्टर के लिए 275 रुपए से 950 रुपए तक का चार्ज लगता था। 5 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे बीएसई पर इंडिगो की ऑपरेटर कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयर 0.12 फीसदी बढ़कर 4927.15 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे।

बाजार से अभी बहुत बड़े मुनाफे की उम्मीद न रखें, संभलकर लगाएं पैसा

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली



भारतीय शेयर बाजार में पिछले दो सालों का दौर निवेशकों के लिए आसान नहीं रहा है। एकमुश्त रकम लगाने वाले निवेशकों को नुकसान झेलना पड़ा है, जबकि एसआईपी के जरिए पैसा लगाने वालों को भी बेहद मामूली रिटर्न मिला है। इस सुस्त माहौल के बीच आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व सीआईओ एस नरेन ने बाजार की जमीनी हकीकत सामने रखी है। उनका कहना है कि इस समय पूरी दुनिया में अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की एकतरफा तेजी हावी है। इसी वजह से भारत जैसे विकासशील बाजारों से विदेशी पूंजी खिंचकर उधर जा रही है। लेकिन ये स्थिति हमेशा ऐसी ही नहीं रहेगी। जैसे ही अमेरिकी कंपनियों का ये एआई बूम सुस्त पड़ेगा, विदेशी निवेशकों की नजरें एक बार फिर मजबूत आर्थिक विकास वाले भारत पर टिक जाएंगी। वैश्विक स्तर पर शेयर बाजार इस वक्त काफी महंगे दौर में कारोबार कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि जब बाजार जरूरत से ज्यादा महंगे हो जाते हैं, तो उनमें कभी न कभी गिरावट या करेक्शन आना तय होता है। एस नरेन का मानना है कि दुनिया भर का बड़ा निवेश इस समय अमेरिका के एआई सेक्टर की तरफ लगा हुआ है। इसके साथ ही दुनिया में कई जगह तनाव भी बना हुआ है। यही वजह है कि भारत समेत कई उभरते बाजारों में विदेशी निवेशक खुलकर खरीदारी नहीं कर पा रहे हैं। ये दबाव सिर्फ भारत पर ही नहीं है, बल्कि ताइवान और कोरिया जैसे बड़े बाजारों से भी विदेशी पैसा बाहर निकला है। अगर अमेरिकी एआई सेक्टर की ये रफ्तार ऐसे ही जारी रही, तो भारतीय बाजार पर कुछ समय और दबाव बना रह सकता है।

जॉर्जिया में होमकमिंग पार्टी के दौरान गोलीबारी, 2 लोगों की मौत; 35 लोग घायल

हिंदमाता नेटवर्क @ जॉर्जिया

जॉर्जिया में रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान गोलीबारी में दो लोगों की गोली लगने से मौत हो गई और करीब 35 अन्य लोग घायल हो गए। जॉर्जिया जांच ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि शनिवार देर रात करीब 1:25 बजे एक कार्यक्रम के दौरान डूली काउंटी शेरिफ कार्यालय के अधिकारी गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने गोलियां चलने की आवाज सुनी। अधिकारियों ने बताया कि घटनास्थल पर दो लोग मृत मिले और कई अन्य लोग गोली लगने से घायल थे। पुलिस ने यह साफ नहीं किया कि घायल हुए 35 लोगों में से कितने लोगों को गोली लगी थी और न ही उनकी चोटों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जॉर्जिया जांच ब्यूरो ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए कई अस्पतालों में ले जाया गया।

जॉर्जिया के वियना में होमकमिंग पार्टी

दरअसल, अधिकारियों के मुताबिक, रविवार की सुबह जॉर्जिया के वियना में एक होमकमिंग पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक, जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि यह गोलीबारी रात करीब 1:25 बजे एक ब्लॉक पार्टी के दौरान हुई, जिसमें 1,000 से ज्यादा लोग शामिल थे और पुलिस अधिकारी भीड़ पर नजर रख रहे थे।

जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा जांच



डूली काउंटी के कोरोनर ब्रेट वॉल्स ने पुष्टि की कि मारे गए लोग 20 और 23 साल के पुरुष थे। उनके नाम अभी जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि जांच चल रही है। डूली काउंटी के शेरिफ क्रेग पीवी ने बताया कि कम से कम 25 लोगों को अस्पताल ले जाया गया और एक ब्लॉक की दूरी पर दो जगहों पर गोलीबारी की सूचना मिली। जॉर्जिया ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जांच में स्थानीय अधिकारियों की मदद कर रहा है।

पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई के लिए आंदोलन शुरू

इस्लामाबाद में धारा 144 लागू; 2 हजार कार्यकर्ता गिरफ्तार, संसद-हाईवे सील



हिंदमाता नेटवर्क @ इस्लामाबाद

पाकिस्तान में एक बार फिर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का एक बड़ा मार्च खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद की ओर जा रहा है। ये मार्च सरकार के साथ बातचीत नाकाम रहने के बाद निकाला गया है। वहीं, इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसी को भी इस्लामाबाद में घुसने की इजाजत नहीं जाएगी। आसिम मुनीर की टेंशन बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि ये मार्च इस्लामाबाद पहुंच पाएगा या सरकार इसे बीच रास्ते में ही रोक लेगी?

दो दौर की बातचीत के बाद भी नहीं बनी सहमति

इससे पहले सरकार के वाताकारों और इमरान खान की पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत का दूसरा दौर शनिवार शाम 4 बजे शुरू हुआ और रातभर चला। यह बातचीत रविवार तड़के बिना किसी सहमति के समाप्त हो गई।

2 हजार कार्यकर्ता गिरफ्तार, संसद-हाईवे सील

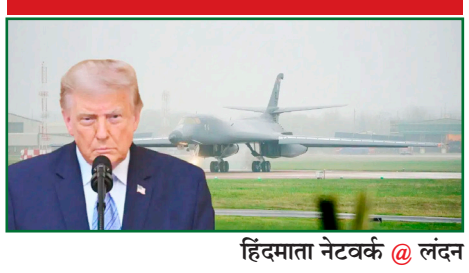
पीटीआई के समर्थकों ने खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवत से लॉन्ग मार्च शुरू किया। रविवार 4 अक्टूबर से ही शुरू हुए इस मार्च में बड़ी संख्या में पीटीआई समर्थक गांडी चौक पर जमा हुए और यहां से मार्च में शामिल हुए। हजारों लोग करीब 275 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। इमरान की पार्टी पीटीआई के कार्यकताओं की बड़े पैमाने पर धरपकड़ की गई। पीटीआई का दावा है कि उसके लगभग 2 हजार कार्यकताओं की गिरफ्तारी की गई है। वहीं, इस्लामाबाद में संसद और हाईवे की सुरक्षा बढ़ाते हुए कई रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है।

पहले 27 सितंबर को होना था मार्च

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने पिछले महीने 27 सितंबर को इस्लामाबाद तक मार्च निकालने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में शहबाज सरकार द्वारा विरोध-प्रदर्शन रोकने के लिए उठाए गए कड़े कदमों के कारण इसे 4 अक्टूबर तक टाल दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान की सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी पड़ा है। पीटीआई के नेताओं की मांग है कि उन्हें जेल में इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए।

ब्रिटेन के एयरबेस से अमेरिका ने हटाए सभी बॉम्बर विमान

ईरान पर हमले के बीच क्यों लिया फैसला?



हिंदमाता नेटवर्क @ लंदन

अमेरिका ने ब्रिटेन के आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस से अपने सभी बॉम्बर विमान वापस बुला लिए हैं। इस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले के लिए किया था। अमेरिका ने यह फैसला ब्रिटेन में इस एयरबेस पर आतंकी हमले की साजिश की जांच के बीच लिया है। पेंटागन के एक अधिकारी के मुताबिक, अमेरिकी बॉम्बर्स को वापस अमेरिका में उनके सैन्य ठिकानों पर भेज दिया गया है। एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह जानकारी दी। मिलिट्री एयर ट्रैफिकिंग अलायंस जैसे विमान गतिविधियों पर नजर रखने वाले समूहों ने ईरान युद्ध शुरू होने के शुरूआती दिनों से आरएएफ फेयरफोर्ड पर दर्जनों बी-52 और बी-1 बॉम्बर विमानों को देखा था। रविवार को भी कई बी-1 बॉम्बर विमानों ने इस एयरबेस से उड़ान भरी। आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस लंदन से करीब 160 किलोमीटर पश्चिम में है। अमेरिका कई दशकों से मिडिल ईस्ट के युद्धों में इस एयरबेस का इस्तेमाल करता रहा है।

आतंकी हमले की साजिश से बढ़ी चिंता

ब्रिटेन में संभावित आतंकी हमले की साजिश की जांच के बीच अमेरिकी विमानों को वापस बुलाया गया है। पिछले हफ्ते दोहरी ब्रिटिश-ईरानी नागरिकता वाले एक व्यक्ति को लंदन में आतंकी हमले की साजिश रचने के शक में गिरफ्तार किया गया था। सितंबर के आखिर में आरएएफ फेयरफोर्ड एयरबेस पर सुरक्षा से जुड़ी एक घटना हुई थी।

कांगो नदी में बड़ा हादसा, नावों की टक्कर में कम से कम 30 लोगों की मौत; दर्जनों लापता

हिंदमाता नेटवर्क @ कांगो



कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में कांगो नदी पर रविवार को दो मोटर चालित लकड़ी की नावों के बीच हुई भीषण टक्कर में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। स्थानीय अधिकारियों ने सोमवार को हादसे की जानकारी दी। बीते महीने, कांगो के बकावु शहर में 2 स्कूलों में भीषण आग लगने से कम से कम 26 छात्रों की मौत हो गई थी और दर्जनों घायल हो गए। मृतकों में 19 लड़कियां और 7 लड़के थे। इक्वेटर प्रांत के प्रांतीय गृह मंत्री क्रिस्पिन मपुतु के मुताबिक, यह नाव हादसा नगोंबे-लुकोलेला इलाके के पास हुआ। दुर्घटना के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। मपुतु ने बताया कि हादसे में मारे गए 30 लोगों को दफना दिया गया है। दुर्घटना के बाद लापता लोगों की तलाश और संभावित जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए अभियान जारी है।

बढ़ सकती है मृतकों की संख्या, खोज अभियान जारी

अधिकारियों के अनुसार, एक नाव उत्तर-पश्चिमी इलाके उबांगी से राजधानी किंशासा की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी नाव किंशासा से लुकोलेला जा रही थी। दोनों नावों की टक्कर उस क्षेत्र के पास हुई, जहां से लुकोलेला पहुंचा जाता है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई लोग अभी भी लापता हैं। राहत और बचाव दल कांगो नदी में खोज अभियान चला रहे हैं।

नाइजीरिया में बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट हादसा, 32 लोगों को लेकर जा रहा विमान क्रैश



हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली

दक्षिणी नाइजीरिया में सोमवार को एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें 25 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर सवार थे। इसके बाद तेजी से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कोई नुकसान हुआ है या नहीं। नाइजीरिया के नागरिक उड्डयन मंत्री फेस्टस केयामो ने एक बयान में कहा कि एयरक्राफ्ट नाइजीरिया के इकोनॉमिक हब लागोस के लिए एक रूटीन मिशन पर था, जब यह ओंडो राज्य के इगबोकोडा इलाके में क्रैश हो गया। नाइजीरियाई एयर फोर्स ने एयरक्राफ्ट की पहचान एटीआर-42 के तौर पर की और कहा कि तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यह तुरंत साफ नहीं हो पाया कि एयरक्राफ्ट को कितना नुकसान हुआ है।

सुबह 9 बजे रडार से गायब हुआ था सैन्य विमान

केयामो ने कहा कि एयरक्राफ्ट सबसे पहले लोकल टाइम के हिसाब से सुबह करीब 9 बजे रडार से गायब हुआ था और पता चला कि यह एडो राज्य से लागोस की अपनी ट्रिप के बीच में ही क्रैश हो गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ओंडो स्टेट पुलिस कमांड के प्रवक्ता डीएसपी अबायोमी जिमोह ने अकुरे में पत्रकारों को घटना की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि घटना से जुड़ी डिटेल्स अभी भी सामने आ रही हैं और पूरी स्थिति का पता लगाने की कोशिशें जारी हैं।

कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट, 90 डॉलर के करीब पहुंचा 1 बैरल का भाव

हिंदमाता नेटवर्क @ नई दिल्ली



निवेशकों द्वारा मिडिल ईस्ट में बढ़ते जोखिमों और ओपेक प्लस की स्थिर प्रोडक्शन पॉलिसी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच, सोमवार को कच्चे तेल की कीमतें भारी गिरावट के साथ 90 डॉलर प्रति बैरल के करीब आ गईं। आज सुबह 11:22 बजे के करीब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर 19 अक्टूबर की डिलीवरी वाले कच्चे तेल की कीमतें 2.71 प्रतिशत (242 रुपये) की भारी गिरावट के साथ 8674 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रही थीं। हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में कच्चे तेल ने 8665 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार की शुरुआत की थी, जो पिछले हफ्ते गुरुवार को 8916 रुपये प्रति बैरल के भाव पर बंद हुआ था। बताते चलें कि शुक्रवार को गांधी जयंती के मौके पर एमसीएक्स बंद था। आज कारोबार के दौरान, कच्चे तेल की कीमतें 8720 रुपये प्रति बैरल के इंट्राडे हाई से लेकर 8644 रुपये प्रति बैरल के इंट्राडे लो तक पहुंच चुके थे।

अमेरिका से दुबई तक सफल रोडशो के बाद जियो आईपीओ को हरी झंडी

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई



मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के बहुप्रतीक्षित आईपीओ को लेकर बाजार में हलचल बढ़ गई है। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक प्रस्तावों में शामिल बताए जा रहे इस इश्यू को लेकर अब एक अहम अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी अक्टूबर में ही बाजार नियामक सेबी के पास आईपीओ के अंतिम दस्तावेज जमा कर सकती है। विदेशों में निवेशकों के साथ रोडशो पूरा होने के बाद कंपनी अब भारत में अगले चरण की तैयारी कर रही है। बैंकिंग सूत्रों के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग 12 ट्रिलियन रुपये या उससे अधिक के आधार बिजनेस वैल्यूएशन पर होने की संभावना जताई जा रही है। कंपनी दशहरा से पहले एंकर राउंड शुरू कर सकती है और 23 अक्टूबर से पहले आईपीओ खुलने की उम्मीद है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब जियो के इश्यू की तारीख, वैल्यूएशन और संभावित लिस्टिंग पर टिकी है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स ने अमेरिका समेत कई विदेशी बाजारों में संभावित निवेशकों के साथ रोडशो पूरा कर लिया है। अब कंपनी 12 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में आईपीओ के अंतिम दस्तावेज सेबी के पास जमा कर सकती है। बैंकिंग सूत्रों का कहना है कि विदेशी निवेशकों से मिले रिस्पॉन्स को देखते हुए जियो प्लेटफॉर्म्स की बेस बिजनेस वैल्यूएशन 143-146 अरब डॉलर के बीच रह सकती है। भारतीय मुद्रा में यह रकम कम से कम 12 ट्रिलियन रुपये के बराबर बैठती है। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के विदेशी रोडशो अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, हांगकांग और सिंगापुर में आयोजित किए गए इन बैठकों में कंपनी की ओर से रिलायंस जियो के चेयरमैन और जियो प्लेटफॉर्म्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश अंबानी तथा रिलायंस रिटेल वेंचर्स की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईशा अंबानी शामिल हुईं। रिपोर्ट के अनुसार, 12 अक्टूबर वाले सप्ताह में भारत में भी आईपीओ को लेकर रोडशो किए जा सकते हैं।

रिलायंस से अलग होते ही शटर डाउन, भारत में बंद होने जा रहे 60 स्टोर्स

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई



देश के रिटेल सेक्टर से एक बड़ी हलचल सामने आई है। दिग्गज कारोबारी कंपनी रिलायंस रिटेल ने दुनिया की सबसे बड़ी कन्वीनियंस स्टोर चेन 7-इलेवन के साथ अपनी 5 साल पुरानी पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला कर लिया है। इस बड़े फैसले के बाद भारत में चल रहे 7-इलेवन के करीब 60 स्टोर्स में से ज्यादातर पर ताला लटकने जा रहा है। जिन चुनिंदा स्टोर्स में अभी काम चल रहा है, वहां भी बचा हुआ सामान बेचकर उन्हें बंद करने की तैयारी की जा रही है। साल 2021 में जब रिलायंस ने 7-इलेवन को भारत लाने का ऐलान किया था, तब इसे रिटेल बाजार में एक नया प्रयोग माना जा रहा था। लेकिन 5 साल के भीतर ही ये विदेशी मॉडल भारतीय बाजार की जमीनी हकीकत के आगे टिक नहीं पाया।7-इलेवन जैसे बड़े ब्रांड को भारत में जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, वो थी यहां की रिटेल बनावट। एक तरफ गली-मोहल्लों में फैली लाखों छोटी किराना दुकानें हैं, जो दशकों से लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर रही हैं। दूसरी तरफ जेप्टो, ब्लिंकइट और इंस्टामार्ट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं, जो 10 मिनट में स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक और राशन घर के दरवाजे पर पहुंचा रही हैं इन दोनों के बीच 7-इलेवन का मॉडल बुरी तरह फंस गया। कन्वीनियंस स्टोर का पूरा कॉन्सेप्ट इस बात पर टिका होता है कि ग्राहक तुरंत की जरूरत के लिए दुकान पर आए। स्टोर बहुत कम खर्च में कर रहा है।

हिंदमाता एंकर फ्रांस में सोमवार को करीब 400 से 500 हाई स्कूलों को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रखने की तैयारी है

पेरिस से शुरू हुई आग पूरे देश में फैल रही... फ्रांस में छात्र गुस्से में क्यों हैं?

हिंदमाता नेटवर्क @ पेरिस

फ्रांस की राजधानी पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में शुरू हुआ छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल गया है। खराब स्कूल व्यवस्था, शिक्षकों की कमी, बड़ी कक्षाओं और सरकार की बजट कटौती की योजनाओं को लेकर छात्र सड़कों पर हैं। प्रदर्शन के दौरान कई जगह पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई है। अब सरकार के सामने कानून-व्यवस्था संभालने के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने की चुनौती भी है। ताजा जानकारी के मुताबिक, फ्रांस में सोमवार को करीब 400 से 500 हाई स्कूलों को पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रखने की तैयारी है। शिक्षा मंत्री एडुआर जॉफ्रे ने कहा कि कई स्कूलों में सुरक्षा की स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है। उनका कहना है कि स्कूलों को बंद करने का फैसला छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

पेरिस के गरीब इलाकों से शुरू हुआ आंदोलन

यह आंदोलन सितंबर के मध्य में पेरिस के आसपास के गरीब इलाकों से शुरू हुआ था। खासतौर पर 'सीन-सेंट-डेनिस' जैसे इलाकों के छात्रों ने स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर आवाज उठाई। छात्रों का कहना है कि कई स्कूलों में जरूरत के मुताबिक शिक्षक नहीं हैं। कई कक्षाओं में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है और कुछ स्कूलों की इमारतें भी खराब हालत में हैं। पेरिस के उत्तर में स्थित 'ऑबर्विलियर्स' जैसे इलाकों के छात्रों ने कहा कि उन्हें अमीर इलाकों के छात्रों के मुकाबले कम सुविधाएं मिल रही हैं। कुछ छात्रों ने यह भी शिकायत की है कि शिक्षकों की कमी के कारण पूरे विषय की पढ़ाई नहीं हो पाती और इसके बावजूद उनसे परीक्षाओं में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की जाती है।



1,200 से ज्यादा स्कूलों तक पहुंचा विरोध

कुछ ही दिनों में यह आंदोलन पेरिस से निकलकर फ्रांस के दूसरे शहरों तक पहुंच गया। इस सप्ताह 1,200 से ज्यादा हाई स्कूलों में विरोध या प्रदर्शन देखने को मिला। छात्रों ने कई जगह स्कूलों के गेट बंद कर दिए और कक्षाओं को रोकने की कोशिश की। शुक्रवार को करीब 400 स्कूल बंद थे, जबकि 560 स्कूलों में प्रदर्शन या अन्य तरह की गतिविधियों के कारण पढ़ाई प्रभावित हुई। कुछ जगह छात्रों ने सड़क पर आगजनी की और पुलिस के साथ झड़प भी हुई। पेरिस के कुछ स्कूलों के प्रवेश द्वारों के पास आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं।

पुलिस से झड़प और हजारों गिरफ्तारियां

प्रदर्शन का एक बड़ा हिस्सा अब हिंसा में बदलता दिखाई दे रहा है। कई शहरों में पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कुछ जगह छात्रों और पुलिस के बीच पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुईं। पुलिस ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने प्रदर्शन में हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। पेरिस के पुलिस प्रमुख ने 3 अक्टूबर को कहा कि छात्र आंदोलन नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है और प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की अपील की।

सिर्फ शिक्षा नहीं, बजट भी बड़ा मुद्दा

फ्रांस में चल रहा यह आंदोलन ऐसे समय में तेज हुआ है जब सरकार ने 2027 के बजट में खर्च कम करने की योजना पेश की है। सरकार आर्थिक घाटे को नियंत्रित करना चाहती है, लेकिन बजट कटौती को लेकर कर्मचारियों, यूनियनों और छात्रों में नाराजगी है। 30 सितंबर को सरकारी कर्मचारियों ने भी वेतन और बजट कटौती के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन किया था। इसमें शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, दमकल कर्मचारी और दूसरे सरकारी कर्मचारी शामिल हुए।

दैनिक ठाणे, मंगलवार 6 अक्टूबर, 2026
हिंदमाता मिरर
पैनी नजर, पुख्ता खबर
GAME & GLAMOUR

भुवनेश्वर कुमार बने टीम इंडिया के कप्तान



■ इस टूर्नामेंट में संभालेंगे कमान; क्रुणाल पांड्या को भी मिला मौका

भारतीय क्रिकेट टीम से लगातार बाहर चल रहे भुवनेश्वर कुमार को अचानक से बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भुवनेश्वर को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया है। उनकी कप्तानी में कई जाने-माने नाम खेलते हुए नजर आएंगे। दरअसल, भुवनेश्वर को 30 अक्टूबर से शुरू हो रहे हांगकांग सिक्सस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। भुवनेश्वर टीम इंडिया से लंबे समय से बाहर चल रहे हैं। हालांकि, वह लगातार अपनी गेंदबाजी से वापसी की दावेदारी ठोक रहे हैं। वह आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हैं और टीम को दो खिताब दिलाने में उनका अहम रोल रहा है।

पाकिस्तान से छीनेंगे खिताब

इस टूर्नामेंट का मौजूदा विजेता पाकिस्तान है और भारत की कोशिश होगी पाकिस्तान को पछाड़कर ये ट्रॉफी जीतने की होगी। टूर्नामेंट के लिए जो टीम चुनी गई है उसके पास अच्छा खासा अनुभव भी है और युवा जोश भी। भुवनेश्वर की गेंदबाजी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वहीं, उनके अलावा टीम में नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी जैसे तूफानी बल्लेबाज हैं। पांड्या के रूप में दमदार ऑलराउंडर है तो वहीं शशांक के रूप में मैच फिनिश करने वाला खिलाड़ी।

ये खिलाड़ी भी आएंगे नजर

भुवनेश्वर के अलावा इस टीम में आईपीएल में चमकने वाले कई और खिलाड़ी नजर आएंगे। इस टूर्नामेंट के लिए चुनी गई टीम इंडिया में क्रुणाल पांड्या, शशांक सिंह, राहुल तेवतिया, नीतीश राणा, राहुल त्रिपाठी और टी. नटराजन को जगह मिली है। शशांक को छोड़कर इस टीम के बाकी सदस्य टीम इंडिया के लिए खेल चुके हैं। इस टूर्नामेंट में एक टीम में सिर्फ 6 खिलाड़ी ही खेलते हैं और इसे काफी रोमांचक माना जाता है।

मेरी कोई बेनामी संपत्ति नहीं: रकुल

बीते हफ्ते मुंबई इनकम टैक्स विभाग ने बॉलीवुड से जुड़े कई ठिकानों पर अचानक कार्रवाई शुरू की थी। इसके तहत विभाग ने कई बड़े प्रोडक्शन हाउस और फिल्मी हस्तियों के ठिकानों पर जांच शुरू कर दी। मामले में रकुलप्रीत सिंह और वासु भगनानी समेत कई नाम रडार पर आए। 20 से ज्यादा आईटी अधिकारियों की टीम वाशु भगनानी के बांद्रा वेस्ट के पाली हिल के पूजा कासा इमारत पहुंची। आयकर विभाग की छापेमारी के सप्ताहभर बाद आज सोमवार को रुकल प्रीत सिंह ने चुप्पी तोड़ी है।

रकुल बोलीं- मैं जिम्मेदार नागरिक हूं

मुंबई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने संदिग्ध फंड को लेकर 12 जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया था। जांच करने वालों का मानना है कि फिल्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के बहाने कथित तौर पर फंड को विदेश भेजा जा रहा है। मुंबई आयकर विभाग की कई टीमें कथित विदेशी लेन-देन के दस्तावेजों, वित्तीय रेकॉर्ड और विवरणों की जांच कर रही हैं। इस बीच रकुल प्रीत सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर कहा कि वे पूरी ईमानदारी से टैक्स भरती हैं। वे एक जिम्मेदार नागरिक हैं। साथ ही सेना की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखती हैं।

इंडस्ट्री में मेरा कोई 'गॉडफादर' नहीं'

रकुल प्रीत सिंह के हालिया पोस्ट में उनका दुख छलका है। उन्होंने कुछ ऑनलाइन रिपोर्टर पर बिना तथ्यों के खबरों की सनसनी बनाने का आरोप लगाया है। रकुल ने आईडी रेड को लेकर लिखा है कि वह तलाशी मेरे बारे में नहीं थी। मैं बताना चाहती हूं कि मैं आर्म्ड फोर्सेज (सशस्त्र बलों) की पृष्ठभूमि से आती हूं। इंडस्ट्री में मेरा कोई 'गॉडफादर' नहीं था। मैंने अपनी कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है और कानून का पालन करने वाले एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर 20 साल की उम्र से ही अपने टैक्स भरती आ रही हूं।

कहा- गैर-कानूनी विदेशी लेन-देन में शामिल नहीं हूं

एक्ट्रेस आगे लिखती हैं कि मैं निजी तौर पर या किसी प्रोडक्शन हाउस की ओर से किसी भी तरह के गैर-कानूनी विदेशी लेन-देन में शामिल नहीं हूं। मैं यह भी कहना चाहती हूं कि देश या विदेश में कहीं भी, किसी के भी नाम पर मेरी कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। न तो मुझे कभी किसी ने कोई संपत्ति तोहफे में दी है और न ही मैं सिद्धांत के तौर पर ऐसे महंगे तोहफे स्वीकार करती हूं। मैं उन सभी लोगों से अपील करती हूं, जिन्होंने ये झूठी, दुर्भावनापूर्ण और अटकलों पर आधारित खबरें छापी हैं कि वे इन्हें वापस लें और सच्चाई स्पष्ट करें।

कई बार हीरो हद पार कर देते हैं: सोनल चौहान



गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'मिजार्पुरः द मूवी' से बॉलीवुड में अपना कमबैक करने वाली खूबसूरत एक्ट्रेस सोनल चौहान इन दिनों काफी चर्चा में हैं। फिल्म में उनके रोल और एक्टिंग को दर्शकों का काफी प्यार मिल रहा है। अपने सफल कमबैक के बीच सोनल ने हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान अपने करियर, शादी और रिलेशनशिप्स से जुड़े कई अहम सवालों के बेबाकी से जवाब दिए हैं। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया और पूरी फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

ऑनस्क्रीन किसिंग सीन्स पर सोनल की राय

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान सोनल से पूछा गया कि फिल्मों की शूटिंग के समय कई बार इंटीमेट या किसिंग सीन्स करते समय एक्टर्स बहक जाते हैं। इस पर रिएक्शन देते हुए उन्होंने साफ कहा कि अगर भविष्य में उनका पार्टनर इंडस्ट्री से ही कोई एक्टर होता है और शूटिंग के दौरान कोई दूसरी एक्ट्रेस उनके साथ सीन्स में बहक जाती है, तो वे इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उनका मानना है कि एक्टिंग एक प्रोफेशन है, लेकिन ऑनस्क्रीन रोमांटिक सीन्स को देखकर पार्टनर का सहज होना केवल आपसी भरोसे और सुरक्षा पर निर्भर करता है।

सच्चे प्यार की खातिर फिल्में छोड़ने को भी हैं तैयार

इंटरव्यू के दौरान जब उनसे शादी के बाद करियर को लेकर सवाल किया गया, तो सोनल चौहान ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। उनसे पूछा गया कि यदि उनका पार्टनर किसी गैर-फिल्मी बैकग्राउंड से हो और उनकी एक्टिंग को लेकर इनसिक्योर महसूस करे, तो वे क्या करेंगी? इस पर सोनल ने बिना रोके कहा कि वे अपने काम से बेहद प्यार करती हैं, लेकिन अगर वे उस इंसान के साथ सच्चे प्यार में होंगी, तो उसकी खुशी और रिश्ते को बचाने के लिए एक्टिंग छोड़ सकती हैं।

'जन्नत' से डेब्यू करने के बाद लंबे गैप के बाद वापसी

एक्टर इमरान हाशमी के साथ सुपरहिट फिल्म 'जन्नत' से बॉलीवुड में धमाकेदार कदम रखने वाली सोनल चौहान ने अपने करियर में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। पहली ही फिल्म से रातों-रात नेशनल क्रश बनने के बाद भी उन्हें वो मंजिल पाने में समय लगा जिसकी वे हकदार थीं। हाल ही में रिलीज हुई 'मिजार्पुर: द मूवी' में उनकी एंट्री को फैंस उनके करियर का एक बेहतरीन मोड़ मान रहे हैं।

रिलीज से दो महीने पहले श्रद्धा कपूर की 'ईथा' का वीडियो लीक



फिल्म 'स्त्री 2' के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अपने नए प्रोजेक्ट 'ईथा' को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस फिल्म की रिलीज का फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। जून महीने में जब इस फिल्म का टीजर जारी किया गया था, तो दर्शकों ने श्रद्धा के नए लुक की जमकर तारीफ की थी। पहले यह फिल्म 28 अगस्त को बड़े पर्दे पर आने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई। अब रिलीज से ठीक 2 महीने पहले फिल्म के सेट से लीक हुए कुछ अनदेखे वीडियोज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

लाल साड़ी और ट्रेडिशनल लुक में दिखा लावणी लुक

सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो में श्रद्धा कपूर बेहद ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रही हैं। लाल रंग की साड़ी पहने श्रद्धा अपने रोल विठाबाई के रूप में नंगे पैर डांस करती दिख रही हैं। उनके इस ग्रेसफुल अंदाज और भावपूर्ण एक्सप्रेशन्स ने फैंस का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग उनके इस लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इस क्लिप के सामने आने के बाद दर्शकों के बीच फिल्म के पहले गाने को देखने की उत्सुकता कई गुना बढ़ गई है।

श्रेया घोषाल की जादुई आवाज ने ढाया कहर

लीक हुए एक दूसरे वीडियो क्लिप में फेमस सिंगर श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज सुनाई दे रही है। यह एक प्रॉपर लावणी डांस सीक्वेंस है, जिसमें श्रद्धा कपूर विठाबाई बनकर महफिल सजाती दिखेंगी। श्रेया घोषाल के सुरों और अजय-अतुल के म्यूजिक के साथ श्रद्धा के स्टेप्स का यह मेल दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है।

श्रद्धा कपूर लीक से हटकर ट्रांसफॉर्मेशन

लीक वीडियोज को देखने के बाद फैंस अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की कड़ी मेहनत की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि स्क्रीन पर श्रद्धा नहीं, बल्कि केवल उनका रोल ईथा नजर आ रहा है। उनका यह बॉडी लैंग्वेज और लुक इतना अलग है कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा है। डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर, जिन्होंने हाल ही में विक्की कौशल की 'छावा' जैसी फिल्म का डायरेक्शन किया था, इस बायोग्राफिकल ड्रामा को डायरेक्ट कर रहे हैं। यह फिल्म 4 दिसंबर को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देगी, जिसमें रणदीप हुड्डा, जीशान अय्यूब और नाना पाटेकर जैसे दिग्गज कलाकार मुख्य किरदार में नजर आएंगे।

'मुपापा' में हुई 'बंदिश बैंडिट्स' फेम श्रेया चौधरी की एंट्री

लीक से हटकर फिल्में बनाने और अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना इस समय अपनी बैक-टू-बैक आने वाली फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। एक तरफ जहां उनकी फिल्म 'उड़ता तीर' जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है, वहीं अब उनकी आगामी फिल्म 'मुपापा' को लेकर भी जबदस्त अपडेट सामने आया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म की चर्चित सीरीज 'बंदिश बैंडिट्स' से अपनी खास पहचान बनाने वाली प्रतिभाशाली अभिनेत्री श्रेया चौधरी को आयुष्मान खुराना स्टारर नई फिल्म 'मुपापा' में मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना गया है। हालांकि, मेकर्स ने अभी श्रेया चौधरी के किरदार और कहानी के बारे में गोपनीयता बनाए रखी है और किसी भी विवरण का खुलासा नहीं किया है। लेकिन इस नई जोड़ी को बड़े पर्दे पर एक साथ देखना दर्शकों के लिए काफी फ्रेश और रोमांचक अनुभव होने वाला है।

■ फिल्म 'मुपापा' का निर्देशन समीर सक्सेना कर रहे हैं, जिन्होंने 'काला पानी' जैसी शानदार सीरीज का निर्देशन किया था। इस फिल्म का निर्माण यशराज फिल्म्स के सीईओ अक्षय विधानी और 'पोषम पा पिक्चर्स' मिलकर कर रहे हैं। पोषम पा पिक्चर्स की स्थापना समीर सक्सेना, बिस्वपति सरकार, सौरभ खन्ना और अमित गोलानी ने मिलकर की है। मेकर्स के अनुसार, यह फिल्म 19 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। 'मुपापा' के अलावा आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी एक और अनोखी फिल्म 'उड़ता तीर' के प्रमोशन में काफी व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ सारा अली खान मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। हाल ही में फिल्म की रिलीज डेट को लेकर मेकर्स ने एक नया अपडेट शेयर किया है। पहले यह फिल्म 9 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब शेड्यूल में बदलाव करते हुए इसे 23 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज करने का फैसला किया गया है।

'खतरों के खिलाड़ी 15' के विजेता अविनाश मिश्रा

रोहित शेट्टी द्वारा होस्टेड स्टंट बेस्ड रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' एक साल ब्रेक के बाद इस साल अगस्त में वापस आया। 'डर का नया दौर' थीम के साथ इस सीजन में पुराने कंटेस्टेंट्स और नए प्रतिभागियों को एक साथ लाया गया। कई हफ्तों तक मुश्किल स्टंट करने के बाद टीवी एक्टर अविनाश मिश्रा 'खतरों के खिलाड़ी 15' के विजेता बने हैं। अविनाश मिश्रा ने टॉप 3 फाइनलिस्ट ऋत्विक धनजानी और ओरी को हराकर 'खतरों के खिलाड़ी 15' की ट्रॉफी अपने नाम की। खिताब के साथ अविनाश को 20 लाख रुपए का इनाम, यूरोप ट्रिप और एक कार मिली। वहीं, बाकी दो फाइनलिस्ट को बाइक दी गई।



कौन हैं अविनाश मिश्रा?

9 दिसंबर, 1995 को जन्मे अविनाश मिश्रा करीब एक दशक से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। एक्टर बनने से पहले वह डीजे के तौर पर काम करते थे। अविनाश ने साल 2016 में 'सेठजी' शो से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। शो में उन्होंने 'बाजीराव' का किरदार निभाया। इसके बाद वह साल 2017 में 'इश्कबाज' में नजर आए। साल 2018 में अविनाश के काम को 'मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव' में काफी पहचान मिली।

2022 में आया टर्निंग पॉइंट

अविनाश मिश्रा के करियर में बड़ा बदलाव साल 2022 में आए शो 'नाथ' से आया। इसकी सफलता के बाद अभिनेता 2024 में 'बिग बॉस 18' में नजर आए, जहां वह मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक रहे और चौथे स्थान पर रहे। 'बिग बॉस 18' के घर में रहते हुए ही अविनाश को 'खतरों के खिलाड़ी 15' के कंटेस्टेंट के तौर पर फाइनल कर लिया गया था।

ईशा सिंह के साथ जुड़ा नाम

बता दें कि जब अविनाश मिश्रा 'बिग बॉस 18' में थे, तो उनका नाम उसी शो की कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस ईशा सिंह के साथ जुड़ा। शो के अंदर दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, शो खत्म होने के बाद भी दोनों कई बार साथ में नजर आए। हालांकि, हर बार अभिनेता इस बात से इनकार करते रहे हैं और कहा की वह बहुत अच्छे दोस्त हैं।

शमी की वापसी मुश्किल!



वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे में मुश्किल परिस्थितियों के बीच शानदार पारी खेलने वाले रोहित शर्मा की पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने जमकर तारीफ की है। कार्तिक ने कहा कि रोहित की यह पारी बताती है कि दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 वनडे विश्व कप में वह भारतीय टीम के लिए कितने महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। वहीं, मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में वापसी को लेकर कार्तिक ने साफ तौर पर कहा कि टीम उनसे आगे बढ़ चुकी है और अब उन्हें वापस लाने का कोई मतलब नहीं है।

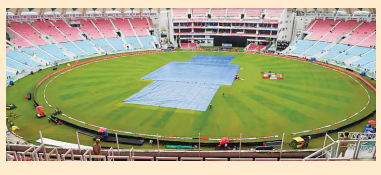
2027 विश्व कप में अनुभव आएगा काम

कार्तिक ने कहा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ रोहित ने जिस तरह अपनी आक्रामक प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखा, वैसी ही परिस्थितियां 2027 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका में भी सामने आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में रोहित, शुभमन गिल और विराट कोहली जैसे अनुभवी खिलाड़ियों का अनुभव भारत के काम आ सकता है। उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी मुश्किल समय में जरूरत से ज्यादा शॉट खेलने की गलती कर सकते हैं, लेकिन रोहित अब अपने अनुभव के कारण यह समझते हैं कि कब रक्षात्मक होकर खेलना है और कब तेजी से रन बनाने हैं। पूर्व भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने भी रोहित की पारी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को शुरुआत में पिच से मदद मिल रही थी, लेकिन रोहित ने कई गेंदों को छोड़कर परिस्थितियों को समझा और ऋतुराज के साथ मजबूत साझेदारी की। इसके बाद उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ तेजी से रन बनाए।

आज भिड़ेंगे भारत और वेस्टइंडीज

भारत बनाम वेस्टइंडीज के दरम्यान 5 मैचों की टी-20 सीरीज का आगाज कल यानी मंगलवार, 6 अक्टूबर से होने जा रहा है, जिसका पहला मुकाबला लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 बजे किया जाएगा। इस बीच क्रिकेट फैंस के लिए थोड़ी बुरी खबर सामने आई है। मौसम विभाग के अनुसार, पहले ही मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है।

6 अक्टूबर को लखनऊ के मौसम का हाल



एक्यूवेदर के अनुसार, लखनऊ में 6 अक्टूबर को गरज-चमक के साथ 68 प्रतिशत बारिश की संभावना है। इसके साथ ही दक्षिण-पूर्व से करीब 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही रहेगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में मौसम मैच में खलल डाल सकता है। हालांकि फैंस को ज्यादा परेशान होने की जरुरत नहीं है, क्योंकि दिन के मुकाबले शाम के समय बारिश कम होने के आसार हैं।

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक नरेश पी. बजाज द्वारा बैरक नंबर 887/27 सेक्शन 18, उल्हासनगर -421 003, जिला ठाणे से प्रकाशित व सोमानी प्रिंटिंग प्रेस, गाला नं. 4, आमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट, सोनवाला क्रॉस रोड -2, जवाहरनगर के पास, फाटक पुल, गोरेगांव, मुंबई -63, (महाराष्ट्र) से मुद्रित।
दूरध्वनि: 0251- 3238100, **कार्यकारी संपादक:** पंजू बजाज (पी. आर. बी. एक्ट के तहत कंटेट चयन के लिए जिम्मेदार) न्याय क्षेत्र ठाणे जिला। **hindmatamirror1@gmail.com RNI. NO. MAHHIN/2011/43060 स्थानीय संपादक:** शिवप्रताप